



महिला टी-20 रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंची शेफाली

>> 14

सरोकार

पर्दे पर गद्दी कैंसर सर्वाइवर्स की जीत की कहानियां

लखनऊ : लखनऊ की छात्रा नीलू शर्मा ने कैंसर का भय कम करने व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कैंसर सर्वाइवर्स की जीत की कहानियां पर्दे पर गद्दी है। उनकी बनाई तीन शॉर्ट फिल्मों में से एक राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। (पेज-10)



जागरण विशेष

सात किमी लंबी पंगत, 10 लाख ने खाया...

इंदौर : ऐसा भोज विरले ही देखने को मिलता है। सात किमी लंबी सड़क पर दो पांतों में बैठ 10 लाख लोगों ने भोजन किया। परोसने का जिम्मा 10 हजार लोगों ने संभाला। भोजन परोसने के लिए वाहनों का प्रयोग किया गया। (पेज-10)



न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

दोबारा कांग्रेस की कमान संभालने को राजी नहीं राहुल

नई दिल्ली : कांग्रेस के तमाम छोटे-बड़े नेता भले ही राहुल गांधी से फिर से संगठन की बागडोर संभालने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहुल फिलहाल अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए राजी नहीं हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने इस इरादे का स्पष्ट संदेश दे दिया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया पर पावंदी हटी

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी हटा दी गई है। राज्य के लोग करीब सात माह बाद मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट सेवा केवल पोस्टपेड मोबाइल सिम पर बहाल रहेगी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

क्रिंटोकॉरेंसी से प्रतिबंध हटा, अब सरकार पर नजर

नई दिल्ली : आम जनता को भौतिक मुद्रा से आजादी देने के नारे से शुरू की गई वर्चुअल मुद्रा यानी क्रिंटोकॉरेंसी के भारत में प्रचलन को लेकर अनिश्चितता फिलहाल खत्म हो गई है। क्रिंटोकॉरेंसी के काराबार से जुड़ी सेवा देने पर भारतीय बैंकों व वित्तीय संस्थानों पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

चार दिन भी नहीं चला अमेरिका व तालिबान के बीच समझौता

काबुल : अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका-तालिबान के बीच हुआ समझौता चार दिन भी नहीं चला। तालिबान ने मंगलवार रात कुंदुज व उरुजगान जिले में हमला कर सेना और पुलिस के 20 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। बौखलाए अमेरिका ने बुधवार को दक्षिण हेलमंड प्रांत में आतंकी संगठन के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए।

सम्मान

पूर्वोत्तर रेलवे इस बार खास तरह से मनाने जा रहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आठ मार्च को महिलाओं के हाथ में होगी रेलवे की कमान

महिला दिवस पर आधी आबादी के जिम्मे पूरी ट्रेन

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे इस बार खास तरह से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहा है। रेलवे ने अबकी आठ मार्च को एक यात्री ट्रेन और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को पूरी तरह महिलाओं के हाथ में सौंपने की तैयारी की है। इसके तहत ट्रेन के संचालन से लेकर सिग्नल, टिकट, सुरक्षा और स्वच्छता तक की जिम्मेदारी महिला कर्मियों के हाथ में ही होगी। यानी लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड, कोच कंडक्टर, टिकट निरीक्षक, टिकट परीक्षक, कोच अटेंडेंट, सफाईकर्मी और सुरक्षाकर्मी के तौर पर जहां महिलाएं नजर आएंगी, वहीं ट्रेन को सिग्नल भी महिलाओं से ही मिलेगा।

गोरखपुर स्टेशन प्रबंधन ने इस खास और अविस्मरणीय यात्रा के लिए रूट और ट्रेन पर फैसला कर लिया है। महिलाओं को गोरखपुर-नौतनवां रूट पर पैसेंजर ट्रेन नंबर 55141 की कमान सौंपी जाएगी। महिला कर्मियों के

संचालन और सुविधाओं में व्यवधान न आने को लेकर पूरा महकमा करेगा सहयोग

सिग्नल, टिकट, सुरक्षा और स्वच्छता तक की जिम्मेदारी रहेगी महिलाकर्मियों के हाथों में

महिला दिवस पर विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत महिलाकर्मियों के नेतृत्व में ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे में महिलाओं के लिए 10 मार्च तक अन्य विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

– पंकज कुमार सिंह, सीपीआरओ, एनई रेलवे

लिहाज से यह इस ट्रेन को उपयुक्त माना जा रहा है। यह ट्रेन सुबह आठ बजे गोरखपुर से रवाना होकर शाम तक वापस आ जाती है। हालांकि ट्रेन के संचालन और यात्रियों की सुविधा में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए रेलवे का पूरा महकमा महिला कर्मियों के सहयोग में रहेगा।

राष्ट्रीय संस्करण

कोरोना का बढ़ा प्रकोप, देश में 29 लोग संक्रमित

सतर्कता ▶ विदेश से आने वाले हर यात्री की अनिवार्य स्क्रीनिंग

संक्रमित पाए गए हर व्यक्ति के तीन किलोमीटर के दायरे में जागरूकता अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 29 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है। तादाद बढ़ने के बाद सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह हरकत में आ गई है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में इस वायरस के निपटने की तैयारियों की समीक्षा और मंत्रिमंडलीय समूह के साथ हालात पर चर्चा की। दूसरी तरफ पीएमओ ने मोर्चा संभालते हुए सभी विभागों को पूरी मुस्तेदी के साथ काम पर जुटने का निर्देश दिया। सरकार ने विदेश से आने वाले हर नागरिक के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाह या चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। अब तक अनिवार्य स्क्रीनिंग केवल 12 देशों से आने वाले यात्रियों की जा रही थी। सरकार देश में 19 नए टेस्टिंग लैब खोलने के साथ देश के बाहर पहली टेस्टिंग लैब खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के तीन किलोमीटर के दायरे में विशेष जागरूकता और सतर्कता बरतने का फैसला लिया गया है।



कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के संबंध में बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (बाएं) और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

हर्षवर्धन ने कहा कि इटली से आए दिल्ली के निवासी से उसके आगरा के छह रिश्तेदारों तक कोरोना वायरस पहुंच गया। वहीं जयपुर में इटली के जिस पर्यटक पति-पत्नी को कोरोना ग्रसित पाया गया था, उनके गृध से अन्य सदस्य व उनके ड्राइवर में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है। शाम होते-होते गुरुग्राम में पेटोएम कंपनी के एक कर्मचारी में भी वायरस की पुष्टि हो गई। इन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल 29 लोगों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हर्षवर्धन ने बताया कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलंस प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्तियों के संपर्क में आने वालों

की पहचान कर उन पर निगरानी शुरू कर दी गई है। इस बीच, विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधर ने लोकसभा में बताया कि अब तक विदेश में 17 भारतीय नागरिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 16 मामले जापान में एक क्रूज शिप के हैं और एक मामला यूएई का है।

वायरस का प्रसार रोकने के लिए क्लस्टर प्रोच: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्लस्टर प्रोच को अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से ग्रस्त पाए जाने के बाद उसके चारों ओर तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों को इसके

इन मामलों की हुई पुष्टि

दिल्ली के मयूर विहार का निवासी व आगरा में रहने वाले उसके छह रिश्तेदार, तेलंगाना का एक व्यक्ति, राजस्थान में इटली के 16 पर्यटक व उनको सफर कराने वाला ड्राइवर तथा गुरुग्राम में पेटोएम कंपनी का एक कर्मचारी। इनके अलावा केरल में तीन लोगों में वायरस की पुष्टि हुई थी, जो अब ठीक हो चुके हैं। दिल्ली वाले मरीज के संपर्क में आए 66 और तेलंगाना वाले मरीज के संपर्क में आए 88 लोगों की पहचान हुई है।

प्रेट

बारे में सचेत किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन व सामुदायिक भागीदारी से उस क्षेत्र के सभी लोगों की निगरानी की जाएगी। इसके तहत देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर इसके हॉट-स्पॉट की पहचान कर वहीं उसे फैलने से रोकने के लिए संसाधनों का प्रबंध किया जाएगा। नही रहेगी चूक की गुंजाइश : इटली और यूएई से आने वाले जो लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं, वे 21-22 फरवरी को ही भारत आ गए थे, उस समय इन दोनों देशों को अनिवार्य स्क्रीनिंग में नहीं रखा गया था। इसे देखते हुए सरकार ने अब विदेश से आने वाले हर व्यक्ति के लिए स्क्रीनिंग

कारोबारियों के जेल जाने की नहीं आएगी नौबत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कारोबारियों को 35 तरह के मामलों में अब जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। कारोबार को और आसान बनाने एवं उद्यमियों को कड़े प्रकार की अपराधिक कार्रवाई से राहत देने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने कंपनी संशोधन बिल-2020 को मंजूरी दे दी। इस बिल में कंपनी कानून 2013 के 65 सेक्शन में संशोधन करके 72 प्रकार के बदलाव लाने हैं, जिससे उद्यमियों को कारोबार के दौरान परेशानी नहीं हो।

सरकार उद्यमियों को कई प्रकार के डिफॉल्टर होने की स्थिति में चलने वाले अपराधिक मुकदमों से राहत देना चाहती है ताकि सरकार के प्रति कॉरपोरेट जगत का भरोसा मजबूत किया जा सके। कारोबारियों के 35 प्रकार के टेक्निकल डिफॉल्टर होने की स्थिति में अपराधिक प्रक्रिया से राहत देने के साथ कई मामलों में जेल जाने के प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कानून का पालन करने वाले उद्यमियों को राहत देने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के मामले में भी कंपनियों को राहत दी जाएगी। जिन कंपनियों को सीएसआर के तहत 50 लाख या उससे कम राशि खर्च करना है उन्हें सीएसआर कमेटी के गठन की जरूरत नहीं होगी।

10 बैंकों के विलय का रास्ता साफ नई दिल्ली : सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों को विलय के माध्यम से चार बड़े बैंकों में बदलने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। फैसले के मुताबिक इस वर्ष पहली अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा। (पेज-12)

कारोबार को आसान बनाने के लिए कंपनी कानून में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

कॉरपोरेट जगत के भरोसे को मजबूती देने के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला



नई दिल्ली में मीडिया को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। जागरण

अगर कोई कंपनी किसी वित्त वर्ष में अपनी आय की दो फीसद से अधिक राशि सीएसआर के तहत खर्च करती है तो वह अगले वर्ष दो फीसद से ऊपर की राशि को समायोजित कर सकती है।।

भारतीय कंपनियां अब विदेशी बाजारों में हो सकेंगी सूचीबद्ध: कैबिनेट के फैसले में भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कंपनी कानून में नए प्रावधान के तहत यह संभव हो सकेगा। इस प्रावधान के तहत भारतीय बाजार में सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध दोनों ही प्रकार की कंपनियों को विदेशी बाजार में जाने का मौका मिलेगा।

एयर इंडिया की पूरी हिस्सेदारी खरीद सकेंगे एनआरआई नई दिल्ली : सरकार ने एयर इंडिया की विदेशी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अनिवार्य भारतीयों को कंपनी की 100 फीसद हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दे दी है। पहले उन्हें 49 फीसद हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति थी। (पेज-12)

होली तक संसद के सुचारु रूप से चलने के आसार नहीं

नई दिल्ली : संसद के दोनों सदनों में विपक्ष व सरकार के रुख को देखते हुए होली तक इसके सुचारु रूप से चलने के आसार नहीं है। दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार तीसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। हंगामे के बीच ही लोकसभा में सरकार ने डाइरेक्ट टेक्स पर अपना अहम विधेयक 'डिवाद से विश्वास' पारित तो करा लिया लेकिन हंगामा बरकरार है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और जसबीर सिंह गिल ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्षी नेताओं के इसी मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली हिंसा पर होली के बाद चर्चा कराए जाने के सरकार के अपने तर्क हैं। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि चर्चा के दौरान कोई भी पक्ष ऐसा कोई बयान दे दे जिससे नियंत्रित माहौल फिर से गर्म हो जाए। (पेज-3)

दिल्ली हिंसा की सुनवाई लंबे समय के लिए टालना उचित नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कल सुनवाई करने के लिए कहा

विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाएं तलाशने का भी आग्रह

भाजपा नेताओं पर एफआइआर दर्ज करने की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई से इन्कार

वर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और पीड़ितों को मदद व मामले की जांच एसआइटी से कराए जाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर की भड़काऊ भाषण देने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। सरकार की ओर से हर्ष मंदर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणियां करने के

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कल सुनवाई करने के लिए कहा

विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाएं तलाशने का भी आग्रह

भाजपा नेताओं पर एफआइआर दर्ज करने की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई से इन्कार

वर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और पीड़ितों को मदद व मामले की जांच एसआइटी से कराए जाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर की भड़काऊ भाषण देने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। सरकार की ओर से हर्ष मंदर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणियां करने के

आरोपों पर उनके वकील से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने कहा कि वह पहले बयान के बारे में स्थिति साफ चाहते है उसके बाद ही याचिका पर विचार किया जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट हिंसा मामले पर सुनवाई कर रहा है ऐसे में उन्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। हालांकि कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का इतने लंबे समय तक सुनवाई टालना उचित नहीं था। पीठ ने हाई कोर्ट से मामले पर 13 अप्रैल की जगह छह मार्च यानी शुक्रवार को ही सुनवाई करने को कहा। शीर्ष अदालत ने जल्द से जल्द मामले का मेरिट के आधार पर निपटारा करने को भी कहा है।

दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज हो केस पेज>3

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर समेत सात दोषी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला निवासी सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात आरोपितों को दोषी करार दिया है। चार को बरी कर दिया गया। अदालत 12 मार्च को दोषियों को सजा सुनाएगी।

बुधवार को जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि यह भरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल था। सीबीआई और पीड़िता के वकील धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा ने अच्छा काम किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वहीं कुलदीप सेंगर ने अदालत में निर्दोष होने की गुहार लगाई, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि तुमने खुद को बचाने के लिए तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया पर कामयाब नहीं हो सके। हमें सब दिखता है।

जागरण विचार

आखिर पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर किस मुह से भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई की मांग लेकर उसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने बयान दिया था कि उसने कश्मीर, अयोध्या व एनआरसी के मामले में इंसानियत, समानता और सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की? संविधान बचाने की उनकी बातों का तब कोई अर्थ नहीं रह जाता जब वह कोर्ट के साथ ही संसद पर भी अविश्वास जताते हुए लोगों को सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते हैं। नि:संदेह भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर लगाम लगानी ही चाहिए, लेकिन उन्हें भी बेनकाब किया जाना चाहिए जो संविधान की फर्जी ओट लेकर समाज में जहर घोल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला निवासी सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात आरोपितों को दोषी करार दिया है। चार को बरी कर दिया गया। अदालत 12 मार्च को दोषियों को सजा सुनाएगी।

भारपीठ के बाद न्यायिक हिरासत में हुई थी पीड़िता के पिता की मौत

11 आरोपितों में से चार बरी, 12 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

पीड़ित पक्ष की तरफ से 55 लोगों की गवाही हुई थी, जबकि आरोपित पक्ष की तरफ से नौ गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप को हत्या का आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील ओ दलीलों के बाद उस पर भी ट्रायल हुआ। आरोपपत्र में कहा गया कि पीड़िता के पिता को मारा गया था। उनके शरीर पर 18 जगह चोट आई। इस वजह से घटना के चौथे दिन 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक पर झूठा केस दर्ज किया गया, जो कुलदीप के इशारों पर हुआ था। गैर इरादतन हत्या पेज>>7

न्यूज गैलरी

बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा तय करे सरकार : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के बाद छात्रों व परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के संबंध में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार व पुलिस को निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने पुलिस से कहा कि 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा के केंद्रों पर सुरक्षा तय करें। इस निर्देश के साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। (जास)

दिल्ली हिंसा के पीड़ितों के इलाज में भेदभाव नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली हिंसा के पीड़ितों के औपचारिक भेदभाव के आरोपों को जीटीवी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरह से झूठा और हतोत्साहित करने वाला बताया है। अस्पताल प्रशासन ने यह स्पष्टीकरण अब जारी किया है, जब सोशल मीडिया सहित कई माध्यमों के जरिए अफवाह फैलाई जा रही थी कि अस्पताल में लोगों की जाति और धर्म पूछकर उपचार किया जा रहा है। जीटीवी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, वह हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना काम पूरी तत्परता से बगैर भेदभाव के कर रहे हैं। वहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर किशोर सिंह ने कहा कि किसी भी गंभीर रूप से घायल या बीमार का नाम-पता पूछने से पहले हम उनकी हालत को देखकर उपयुक्त इलाज करते हैं। (जाब्यू)

‘दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा में कुछ भी गलत नहीं’

नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा पीड़ितों के मुआवजे की सरकारी घोषणा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के इस फैसले में कुछ गलत नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। मुख्य पीठ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह योजना सिर्फ दंगा पीड़ितों की मदद के लिए ही होगी। पीठ ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। पीठ ने कहा कि सरकार की ओर से मुआवजा भी गलत आधार पर नहीं दिया जा रहा है। मुख्य पीठ ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता माने भी लीया जाए तो योजना पूरी तरह से अत्यवहारिक हो जाएगी। इसे लागू करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। भाजपा नेता व पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका के अनुसार मुआवजे का भुगतान किए जाने से पहले दंगा पीड़ितों की पहचान की जाए। (जास)

विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में आइआइटी दिल्ली भी

नई दिल्ली, प्रे़ट : क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारत के प्रतिष्ठित आइआइटी बांबे और आइआइटी दिल्ली शामिल हैं। आइआइटी बांबे को 44वां और आइआइटी दिल्ली को 47वां स्थान मिला है। पिछले साल आइआइटी दिल्ली को 61वां और आइआइटी बांबे को 53वां स्थान हासिल हुआ था। इस साल सी सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में आइआइटी कानपुर समेत पांच संस्थान शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश प्रतापसिंह ‘निशंक’ ने बुधवार को बताया कि हमारे प्रमुख इंजीनियरिंग कालेजों के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन संस्थानों ने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार के शिक्षण संस्थानों में शोध और अनुसंधान को लगातार बढ़ावा देने के चलते हुआ है। आइआइटी दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव ने बताया कि कैम्पस में रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने के कारण यह यह नतीजे आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में उठाए गए विभिन्न कदमों के जरिये बाहरी साझेदारों ने हमारी उपलब्धियों का

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे राहुल गांधी

सुना दुख-दर्द ▶ कांग्रेस नेता ने कहा– स्कूल देश का भविष्य, दंगाइयों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित लोगों के घावों पर मरहम लगाया और उनके दुख-दर्द को सुना।

कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी बृजपुरी रोड स्थित अरुण मॉर्निंग पब्लिक स्कूल गए और उसके बाद एक मस्जिद में भी गए। दोनों जगह दंगाइयों ने तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। यह स्कूल कांग्रेस के पूर्व विधायक भीष्म शर्मा का है। बृजपुरी में राहुल ने दंगा पीड़ितों से बात की और उनके दुख दर्द को सुना। पीड़ितों ने उन्हें बताया कि दंगाइयों ने घरों व दुकानों के साथ स्कूलों को भी आग लगा दी। राहुल ने कहा कि स्कूल देश का भविष्य हैं, नफरत और हिंसा ने स्कूल को जलाया है। हिंसा से किसी का फायदा नहीं हुआ है। हिंसा और नफरत एक सिक्के के दो पहलू हैं, यह दोनों ही तरक्की के दुश्मन हैं।

राहुल गांधी मुस्ताफाबाद और शिव विहार सहित अन्य इलाकों में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस वजह से उन्हें



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बुधवार को दंगा प्रभावित उत्तरी दिल्ली के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वह बृजपुरी के एक स्कूल में भी गए जिसे दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। प्रे़ट

वापस लौटना पड़ा।

हिंसा से भारत की छवि को घोट पहुंची : राहुल ने कहा कि देश को बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। इससे भारत माता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबको मिलकर प्यार से काम करना पड़ेगा। इस हिंसा से दुनिया में भारत की छवि को गहरी चोट पहुंची है। भाईचारा और एकता हमारी ताकत थी, उसको यहां जलाया गया है।

ताहिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या के आरोपित आम आदमी पार्टी के निर्लंबित निगम पारद ताहिर हुसैन को मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने व अपराधिक साजिश रचने की धाराओं में चार मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को ताहिर के दो मोबाइल रखने की जानकारी मिली है। कॉल डिटेल से पता चला है कि 24 फरवरी की रात 12 बजे तक वह चांदबाग वाले घर में ही मौजूद था। उस दिन दंगे के दौरान दिनभर में उसने करीब 150 कॉल की थी। हत्या का मुकदमा दर्ज होने पर ताहिर भूमिगत हुआ तो उसकी अंतिम लोकेशन ओखला में थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि वह जामिया, ओखला व आसपास के इलाके में छिपा हो सकता है। वह विदेश न भाग जाए, इसलिए पुलिस जल्द लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। हुसैन के पासपोर्ट के बारे में पता लगाया जा रहा है।

ताहिर की तलाश में दिल्ली पुलिस ने अमरोहा में दबिश दी

जास, अमरोहा : दिल्ली हिंसा के दौरान हुई आइबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपित आम आदमी पार्टी के निर्लंबित पार्षद ताहिर हुसैन की तलाश में बुधवार देर शाम दिल्ली पुलिस उप के अमरोहा पहुंची। हसनपुर के मोहल्ला काला शहीद व ताहिर के पतुकर गांव पौरारा समेत कई स्थानों पर दबिश दी। पौरारा से ताहिर के तहेरे भाई के कालेज में तैनात एक शिक्षक से पूछताछ की। देर रात तक पुलिस की दबिश जारी थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के इन्स्पेक्टर दिग्विजय सिंह व सन लाइट कालोनी थाने के दारोगा मनोज कुमार के नेतृत्व में दो गाड़ियों से आई पुलिस टीम ने हसनपुर कोतवाली पुलिस को साथ लेकर मोहल्ला काला शहीद में दबिश दी।

अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने एसआईटी से मांगा जवाब : ताहिर हुसैन को अग्रिम जमानत याचिका पर कड़कड़हूमा कोर्ट ने पुलिस क्राइम ब्रांच के विशेष जांच दल (एसआईटी) से जवाब मांगा है। इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

हालात सामान्य, अब जांच पर जोर देगी पुलिस

जास, नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। शिव विहार 25 फुटा रोड, ताहिर हुसैन के चांद बाग स्थित घर के आसपास, गली नंबर एक बृजपुरी आदि कुछ इलाके में तनाव बरकरार है। जबकि मौजपुर, करावल नगर, भजनपुर व जाफराबाद में हालात सामान्य हो गए हैं। हालात सामान्य होने पर अब अधिकतर इलाकों से अर्धसैनिक बलों को हटा लिया गया है। दिल्ली पुलिस व पैरा मिलिट्री के जवान अब केवल दंगा प्रभावित इलाकों में वाहनों से गश्त कर रहे हैं। बुधवार तक दंगों के मामले में 531 केस दर्ज किए गए, जिनमें 36 केस हत्या का शामिल हैं।

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एसआईटी दंगों के दौरान हुई हत्याओं की जांच करेगी। हत्या के सभी 36 मामले क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हालात सामान्य होने के बाद अब पुलिस का जोर जांच करने पर होगा। सीसीटीवी फुटेज, पुलिस द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी व लोगों के द्वारा मोबाइल से बनाए गए वीडियो आदि देखकर क्राइम ब्रांच व जिला पुलिस दंगाइयों की पहचान में जुट गई है। पहचान होने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है।

ग्लोबल एजेंसी तैयार करेगी जेवर के स्मार्ट सिटी की डीपीआर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर क्षेत्र में विकसित होने वाले स्मार्ट सिटी की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) ग्लोबल एजेंसी से तैयार कराई जाएगी। शासन स्तर पर हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। स्मार्ट सिटी को लेकर अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा तैयार स्टडी रिपोर्ट का बुधवार को प्राधिकरण अधिकारियों ने शासन में प्रस्तुतीकरण दिया है। प्राधिकरण बोर्ड पहले ही इस रिपोर्ट पर सहमति दे चुका है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीन किमी के दायरे में स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। इसमें ढांचागत सुविधाएं आधुनिक होंगी। सैर सपाटे से लेकर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, होटल, मॉल, मंडी, थीम पार्क आदि विकसित होंगे। यमुना प्राधिकरण ने अर्नेस्ट एंड यंग एजेंसी से स्मार्ट सिटी की स्टडी रिपोर्ट तैयार कराई है। एजेंसी ने दुनिया भर में विकसित की गई स्मार्ट सिटी के आधार पर जेवर क्षेत्र में विकसित होने वाली स्मार्ट सिटी का खाका पेश किया है। प्राधिकरण ने इस रिपोर्ट को बोर्ड के सामने रखा था। बोर्ड से सहमति मिलने के बाद बुधवार को शासन स्तर पर इसका प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके साथ ही

विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं राहुल : भाजपा

नई दिल्ली, प्रे़ट : भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है कि जब उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रही है, कांग्रेस नेता वोट बैंक की राजनीति करने में जुटे हैं। दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों के राहुल के दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया में भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ये बातें कही। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को शहीद अंकेटबल रतन लाल या आइबी अफसर अंकित शर्मा के घर जाने का समय नहीं मिला और न ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी दी।

बिधुडी बोले-इटली से लौटे राहुल पहले जांच करवाई या नहीं : वहीं, भाजपा सांसद रमेश बिधुडी ने दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को पहले तो यह केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, सांसद बताना चाहिए कि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित इटली से लौटने के बाद उन्होंने अपनी जांच करवाई थी या नहीं।



दंगा प्रभावित क्षेत्र गोकुलपुरी स्थित राजकीय विद्यालय में आयोजित पीटीएम के दौरान बच्चों के साथ उपमुख्यमंत्री मनोष सिसोदिया।

जागरण

को सुना और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से स्पष्ट पूछा कि वह घरों से बाहर निकलकर परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देने में डर रहे हैं क्या। बच्चों के दिलों से डर निकालने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों के साथ हंसो मजाक भी किया और संपर्की भी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपने आत्मविश्वास को किसी भी तरह की हिंसा के कारण कमजोर न पड़ने दें, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान

दंगे और कोरोना के कारण केजरीवाल होली नहीं मनाएंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी इस बार होली नहीं मनाएंगे। केजरीवाल ने बुधवार को इस बात की घोषणा की। होली नहीं मनाने का मुख्य कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे हैं। वहीं इसके पीछे उन्होंने कोरोना वायरस भी कारण बताया है। इस हिंसा में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। तमाम लोगों के घर जला दिए गए हैं। बहुत से लोग घर छोड़ कर चले गए हैं। हिंसा के बाद दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान इन हिंसा पीड़ितों में विश्वास बहाली पर है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक व कार्यकर्ता दंगा पीड़ितों की मदद में लगे हैं। दिल्ली संवाद आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला एकदम सही है। जब घरों में आग लगी हो तो कैसे कोई होली मना सकता है। उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में मिल कर होली- ईद मनाते है। मगर यह समय त्योहार मनाने का नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा का हम सब को दुख है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से भी बचाव हम सब के लिए जरूरी है।

होली मिलन समारोहों में हिस्सा नहीं लेंगे भाजपा विधायक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस के चलते दिल्ली भाजपा के नेताओं और विधायकों ने इस बार होली मिलन समारोह में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुडी ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के होली मिलन समारोहों में शामिल न होने के फैसले का सभी विधायक भी अनुसरण करेंगे। बिधुडी ने बताया कि दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक में राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली और देश को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

हिंसा हो जाने से बच्चों के मन में एक डर है, उस डर को उनके दिलों से हर हाल में निकालना होगा।

उन्होंने कहा बच्चों में आत्मविश्वास वापस लाना होगा। 26 व 29 फरवरी की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई थीं, किसी भी बच्चे का भविष्य हिंसा की वजह से खराब न हो उसके लिए दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में विशेष पीटीएम कर रही है। जिससे सीबीएसई द्वारा निर्धारित की गई नई परीक्षा तिथियों के बारे में जानकारी दी जा सके। शिक्षा निदेशालय की सीबीएसई के साथ संवाद के आधार पर ऐसे बच्चों को फिर से परीक्षा का मौका देने की बात भी शिक्षा मंत्री ने कही जो 7 मार्च तक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी से 7 मार्च के बीच जिसने भी परीक्षा छोड़ दी है ऐसे विद्यार्थियों को अपने स्कूलों में पंजीकरण कराना होगा। साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्यों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे ऐसे बच्चों की सही से लिस्ट व रिकॉर्ड तैयार करें जिसकी परीक्षाएं हूट्टी हैं और इसे सीबीएसई के साथ साझा करें। साथ ही शिक्षा निदेशालय को हिंसा पर जाते हैं इसलिए सामान्य कक्षाएं नहीं लग पा रही है। इस वजह से बच्चे अपने शिक्षकों के संपर्क में नहीं है। इन इलाकों में

30 हजार नहीं, तीन लाख करोड़ का हो सकता प्राधिकरणों में घोटाला

कुंदन तिवारी, नोएडा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने नोएडा प्राधिकरण का वित्तीय ऑडिट किया। 400 पेज की रिपोर्ट शासन को सौंपी है। मुख्यमंत्री ने 30 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही है, लेकिन अभी ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण की जांच व रिपोर्ट आनी बाकी है। सही तरीके से कार्रवाई हुई तो निश्चित घोटाला तीन लाख करोड़ का उजागर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर केवल भू-आवंटन ही जांच का प्रमुख केंद्र बिंदु होगा।

सूत्रों के मुताबिक अब उन समाजसेवियों ने मामले में रूचि दिखानी शुरू कर दी है, जिन्होंने वर्ष 2011 से तीनों प्राधिकरण में घोटाले को लेकर तत्कालीन सरकार को घेरा था। उसमें से एक समाजसेवी मुंबई के भाजपा सांसद भी रहे चुके हैं, जिन्होंने दो लाख करोड़ के भूखंड आवंटन के नोएडा में उजागर कर शिकायत आयकर विभाग से की थी। इसमें तत्कालीन प्रदेश सरकार की मुखिया, उनके भाई, नोएडा प्राधिकरण इंजीनियर समेत 13 बिल्डरों के नाम शामिल होने के साक्ष्य को प्रस्तुत किए थे कि कैसे 300 शेल रुपये के शेयरों को पांच हजार रुपये तक कनवर्ट किया गया। उसके बाद पूरा पैसा हवाला के जरिये बाहर भेज, वापस नोएडा में लगवाया गया। हैरानी बात यह रही कि इस अनैतिक व्यवहार में निर्लंबित तक करवा दिया था। जिसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन वर्ष 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो दोबारा से फाइल खुली। जांच नोएडा कर भू-आवंटन किए गए। इसके बाद आयकर भवन पहुंची। आज भी जांच विचाराधीन होने की बात कही जा रही है, लेकिन तत्कालीन जांच अधिकारी का यहां से तबादला हो चुका है। अब

आयोजन

बुधवार को राष्ट्रपति ने 15 कलाकारों को ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया, पुरस्कृत कलाकारों की कलाकृतियां होंगी प्रदर्शित, 22 तक चलेगी प्रदर्शनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार को आयोजित समारोह में 15 कलाकारों को ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी समारोह में पुरस्कृत इन कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आगाज भी बुधवार शाम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत को दर्शाती इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचारणे शरीक हुए। प्रदर्शनी 22 मार्च तक चलेगी।

राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कला मेले का उद्घाटन करते हुए पटेल ने कहा, ‘मैं माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत सभी 15 कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में जो लोग आते हैं



ललित कला अकादमी स्वीड भवन में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में कलाकृति का अवलोकन करते (सबसे बाएं) केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल व उपराज्यपाल अनिल बैजल (बीच में)।

वो कला में रूचि रखने वाले लोग होते हैं। मैं स्वयं भी गांव से हूँ और जब कभी भी समय

मिलता है तो कला व संस्कृति की ही बातें करता हूँ। वहीं पचारणे ने कहा कि प्रदर्शनी

गरीब सवर्णों को अब मेडिकल पीजी में भी मिलेगा आरक्षण

अधिसूचना जारी ▶ देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10 फीसद सीटें आरक्षित

शैक्षणिक सत्र 2020–21 से होगा विद्यार्थियों का दाखिला

ऋषि दीक्षित, कानपुर

देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गरीब सवर्णों को अब मेडिकल की स्नातकोत्तर यानी पीजी कक्षाओं में दाखिले के लिए भी आरक्षण मिलेगा। मेडिकल कार्डसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एमएस व एमडी कोर्सेज की 10 फीसद सीटें आरक्षित कर दी हैं। इसके लिए पीजी में कुल 1775 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें 1498 सीटें गरीब सवर्णों के लिए आरक्षित होंगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 138 सीटें शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों की 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया था। एमसीआइ ने इसी क्रम में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 2019-20 से आरक्षण लागू कर दिया था। अब 2020-

उत्तर प्रदेश में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कनेक्टिंग इंडिया स्क्रीम के तहत रेलवे ने उत्तर प्रदेश में दो नई लाइनों समेत देश में चार नई लाइन परियोजनाओं की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज (इलाहाबाद) से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) के बीच मौजूदा दोहरी लाइन के साथ एक तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा सहजनवा-दोहरीघाट को एकदम नई लाइन के जरिये जोड़ा जाएगा।

अन्य दो परियोजनाओं के तहत असम में बोंगाइगांव-अगुठोरी के बीच मौजूदा एकल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। महाराष्ट्र में वैभववाड़ी तथा कोल्हापुर को नई लाइन बिछाकर रेल संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

पूँजीगत परिय्य बढ़ा : रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले छह वर्षों में रेलवे का पूँजीगत परिय्य तीन गुना बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में पूँजीगत परिय्यय केवल 53,980 करोड़ रुपये था। परंतु 2020-21 के बजट में इसे बढ़ाकर 1,61,042 करोड़ रुपये कर दिया

सीतापुर जेल में ही रहेंगे आजम और अब्दुल्ला



जागरण संवाददाता, रामपुर

धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के जेल शिफ्टिंग को लेकर दाखिल आपति अदालत ने खारिज कर दी है। सांसद और उनके बेटे अब सीतापुर जेल में ही रहेंगे। हालांकि, सांसद की पत्नी के मामले में अदालत ने प्रशासन को यह फैसला करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। सांसद और उनका परिवार धोखाधड़ी के मुकदमे में जेल में हैं। यह मुकदमा अब्दुल्ला के दो जन्मप्रमाण बनवाने को लेकर है। इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने तीनों की कुर्की के आदेश कर दिए थे। इसके बाद 26 फरवरी को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में आत्मसर्पण किया था। तीनों को

बंगाल की सियासत	
	
दिल्ली हिंसा के प्रतिवाद में तृणमूल ने पूरे बंगाल में निकाली रैली, शुक्रवार को भी राज्यभर में निकाली जाएगी रैली	

भाजपा के खिलाफ तृकां का नया अभियान शुरू

राज्य ब्यूरो, कोलकाता	
	
दिल्ली में हिंसा की घटना के प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को बंगाल में ‘बीजेपी छी-छी’ (भाजपा शर्म करो) अभियान शुरू किया। इसके तहत तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कोलकाता सहित राज्य के हर ब्लॉक में दिल्ली नरसंहार के खिलाफ ‘बीजेपी छी-छी’ रैली निकाली और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे राज्य में दोपहर 3 से 4 बजे तक एक घंटे के लिए यह रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आगामी शुक्रवार को भी दिल्ली में हुए नरसंहार के खिलाफ तृणमूल की ओर से पूरे राज्यभर में ‘बीजेपी छी-छी’ रैली निकाली जाएगी।	
ममता ने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमेशा हिंदुत्व की जप करती है, लेकिन असम में उन्होंने हिंदू हटाओ कार्यक्रम चलाया है। उन्होंने असम में एनआरसी की अंतिम सूची का जिक्र करते हुए कहा कि इससे 19 लाख लोगों को	

भाजपा बोली–असली खेल तो अब शुरू हुआ

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा ने दावा किया है कि 15 से 20 विधायक उसके संपर्क में हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन ‘नईदुनिया’ से कहा कि कांग्रेस के 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस विधायक काम नहीं करता वा रहे हैं, इसलिए उनमें असंतोष है। हालांकि, सियासतदार इसे माहौल बनाए रखने वाला बयान बता रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर मिश्रा ने कहा कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। बहरहाल यह सियासी संग्राम एक-दो दिनों में और तेज होने के आसार हैं। भाजपा का कहना है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।	
रामबाई के पति बोले-जबरिया अफवाह फैलाई : मप्र बसपा की निर्लंबित विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार ने कहा कि उनकी पत्नी बीमार बेटी से मिलने के दिल्ली गई थीं, लेकिन अफसोस है कि दिग्विजय ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग से जोड़ दिया।	
ये विधायक भोपाल लौटे : एदल सिंह कंथाना (कांग्रेस), राजेश शुक्ला (सपा), संजीव सिंह कुशवाहा (बसपा) और रामबाई (बसपा)।	

राष्ट्रीय परिदृश्य
<ul style="list-style-type: none">5553 मेडिकल कॉलेज 19,953 पीजी सीटें (एमएस/एमडी)

एवं फैकल्टी की उपलब्धता को देखते हुए सीटें बढ़ाई हैं। इससे सामान्य सीटें प्रभावित नहीं होंगी।मेडिकल कॉलेजों में गरीब सवर्णों के लिए बढ़ाई गई पीजी सीटों पर दाखिला नीट पीजी के जरिये होगा।

अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन को लेकर फिर घमासान

जागरण संवाददाता, अमेठी

अमेठी में सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन को लेकर जारी घमासान का जिन बुधवार को एक बार फिर बाहर आ गया। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसानों की जमीन हथियाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल को संबोधित मांग पत्र कार्यालय को दीवारों पर चसपा किया। मांग पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका की फोटो छपी है। पैंफलेट पर नीचे विस्थापित कृषक संघर्ष समिति कोहार के अध्यक्ष के साथ ही दस किसानों के नाम भी अंकित हैं। इस बीच कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में तकरार भी हुई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाला।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपाइयों को कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने से मना किया, लेकिन नारेबाजी करते हुए वे पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यालय में दाखिल हो गए। इस बीच कांग्रेस के

अतिक्रमण कर बने धर्मस्थलों को 23 तक हटाए सरकार : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को 23 मार्च तक हटाने का सख्त आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। हालांकि सरकार ने कोर्ट से कार्रवाई के लिए एक साल का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इन्कार कर दिया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थान व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक इस आदेश पर कई पहल नहीं की। ऐसे में अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों को तत्काल हटाने की कार्यवाई करनी होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए कोर्ट से एक साल का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने लंबा समय देने से इन्कार कर दिया और 23 मार्च तक मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई सैनी ने बताया कि अदालत ने सांसद के अधिवक्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया है।

फीसद अधिकारी भारतीय सेना में महिलाएं हैं । सरकार की तरफ से पिछले साल राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, 6.7 फीसद नौसैन्य अधिकारी और 13.28 फीसद भारतीय वायु सेना की अधिकारी महिलाएं हैं ।



सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन। ऋषि दीक्षित ने कहा कि पार्टी किसानों को लड़ाई लड़ रही है और यहां भाजपा के लोग कांग्रेस से लड़ रहे हैं। भाजपा के कुछ लोग जबरन कांग्रेस कार्यालय के गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और विरोध में नारेबाजी की, जो गलत परंपरा है। कई साल से चल रहा विवाद : अमेठी के गौरीगंज स्थित कोहार में स्थित सम्राट साइकिल फैक्ट्री की जमीन को लेकर एक दशक से विवाद चल रहा है। कोहार में सम्राट के नाम से साइकिल बनाने की फैक्ट्री स्थापित हुई जो 1990 के आसपास बंद हो गई। देनदारी को लेकर सम्राट फैक्ट्री के मालिक जैन बंधु पर बैंक ने कोर्ट केस किया। जिसके बाद यह जमीन नौलामी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम आ गई। 2012 से ही जमीन को लेकर दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही किसान विरोधी रहा है। वह हमेशा से किसानों को धोखा देती रही है, लेकिन अब किसान उसकी सच्चाई को जान चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में कुलपति की नियुक्ति पर राजभवन–सरकार में टकराव के आसार

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव के आसार बढ़ गए हैं। राजभवन ने बीते दो दिनों में राज्य के दो विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। दोनों ही नियुक्त कुलपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि वालों को कुलपति बनाए जाने से सरकार नाखुश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है, मगर हमारी राय अलग थी। उन्होंने (राज्यपाल) अपना काम कर लिया अब हम अपना काम करेंगे। इसके साथ ही इस बात की चर्चा गर्म हो गई है कि सरकार कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति चयन को लेकर राज्यपाल अनुसुइया उइके और सरकार के बीच कई दौर की बात हुई है, लेकिन एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से मामला लंबे समय से अटक पड़ा था।

प्रोफेसर बलदेव भाई को ठाकरे विधि की



मध्य प्रदेश के आगर में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और गोपाल भागव के काफिले को कोले झंडे दिखाते कांग्रेस कार्यकर्ता। नईदुनिया

	6 भाजपा माफियाओं के साथ मिलकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की लगातार अफसल कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार के पास पूरा बहुमत है। हर बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी भाजपा के मंसूबे मुंगेरिलाल के सपने साबित होंगे। –कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मप्र
	6 मप्र में कांग्रेस सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट भी कांग्रेस जीतेगी। –दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता
	6 कांग्रेस में कई गुट हैं, जो एक-दूसरे को निपटाने में लगे हैं।उनकी लड़ाई दो जान, भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। –शिवराजसिंह चौहान, पूर्व सीएम

ट्रस्ट का नाम ‘इंडो–इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन’ होगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या की पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाने के साथ ही अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से ट्रस्ट गठित करने जा रहा है। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड जिस तरह मुतवल्ली नियुक्त करता है, उसी तरह अयोध्या की इस वक्फ संपत्ति पर यह ट्रस्ट मुतवल्ली की भूमिका निभाएगा। इस ट्रस्ट में नौ सदस्य होंगे। बाद में मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों व उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सुन्नी वक्फ बोर्ड की गुरवार को होने वाली बैठक में ट्रस्ट गठन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार ‘इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन’ नाम से ट्रस्ट का पंजीकरण भी करा लिया गया है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी चीफ ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट में वक्फ बोर्ड के चार सदस्य शामिल किए जा रहें हैं। साथ ही लखनऊ के भी कुछ लोगों के इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीइओ भी

राजीव के जारी किए लाइसेंस का दोबारा सत्यापन करेगी सीबीआइ

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़ : कश्मीर कैंडर के बर्खास्त आइएएस अधिकारी राजीव रंजन द्वारा 2016-17 में कुपवाड़ा के डीसी रहते जारी करीब 30 हजार आम्स लाइसेंस के धारकों को सीबीआइ की स्पेशल सेल नोटिस जारी करेगी और उन्हें दोबारा सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान गड़बड़ मिलने पर उनके कुपवाड़ा भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। सीबीआइ के अनुसार राजीव ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोगों को फर्जी दस्तावेज और बिना सत्यापन के करीब 30 हजार आम्स लाइसेंस जारी किया हैं। चंडीगढ़ से गिरफ्तार राजीव रंजन और 2013 से 2015 तक कुपवाड़ा के डीएम रहे इतरत हुसैन को श्रीनगर कोर्ट में पेश कर 10 दिन के रिमांड में सीबीआइ पूछताछ कर रही है। एजेंसी के अनुसार राजीव रंजन ने प्रति लाइसेंस 8-10 लाख रुपये लिया है। ये लाइसेंस कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लोगों को भी फर्जी कागजातों पर कश्मीरी बतकर दिए थे। चंडीगढ़ सीबीआइ की एक टीम को जोड़कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लाइसेंस धारकों तक पहुंचने में लगी है



▶ ‘मुतवल्ली’ की भूमिका निभायेगा ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में आज आ सकता है प्रस्ताव

इसमें सदस्य होंगे। ट्रस्ट के नौ सदस्य बाद में मुस्लिम समुदाय के देश के प्रबुद्ध व बड़े उद्योगपतियों को नामित करेंगे। ऐसे चार-पांच बड़े व चर्चित नाम बाद में सदस्य के रूप में ट्रस्ट में शामिल किए जाएंगे। अयोध्या में पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण के साथ ही ऐसा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो इंडो-इस्लामिक सभ्यता को प्रदर्शित करेगा। यह केंद्र भारतीय व इस्लामिक सभ्यता पर शोध करेगा। यहां चैरिटेबिल अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरी व समाज की उपयोगिता की अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनके निर्माण व संचालन की पूरी जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट की होगी।

इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन में किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। यह ऐसा ट्रस्ट होगा, जिसे राजनीतिक दलों की छाप से दूर रखा जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड में उनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा।

अहमदाबाद के थानों में लगेगी आंबेडकर की फोटो या प्रतिमा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : महानगर के सभी थानों में अब संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की फोटो या प्रतिमा रखनी होगी। महात्मा गांधी व सरदार वल्लभभाई पटेल की फोटो या प्रतिमा लगाना पहले से ही अनिवार्य था। गुजरात के गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक परिपत्र के मुताबिक, 71वें गणतंत्र दिवस पर राज्य के पुलिस महकमे के कार्यालयों में आंबेडकर की फोटो अथवा प्रतिमा लगाने का निर्णय किया गया था।

अहमदाबाद पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया का कहना है कि अहमदाबाद महानगर के सभी पुलिस थानों में जल्द ही डॉ. भीमराव आंबेडकर की फोटो या प्रतिमा लगवाई जाएगी। गत 28 फरवरी को ही शहर पुलिस ने परिपत्र जारी कर सभी थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द थानों में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा या फोटो लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद लोगों को डॉ. आंबेडकर के बारे में जानकारी देना है।

अक्टूबर 2019 में थानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो या प्रतिमा लगाने का निर्देश जारी किया था। उसके बाद रन फॉर यूनिटी समारोह से पहले सरदार पटेल की फोटो व प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया।

▶ सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हरियाणा ने बाल विवाह निषेध अधिनियम–2006 में किला संशोधन
▶ पॉक्सो एक्ट में पहले से ही कड़ी सजा का प्रावधान, आरोपितों का बचना नामुमकिन

उसके पति के बीच शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म मानते हुए आरोपित पुरुष को सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कर्नाटक विधानसभा की तर्ज पर यह संशोधन किया है।

बता दें कि कर्नाटक राज्य विधान मंडल ने धारा-3 में उपधारा (1क) शामिल की है। बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के अनुसार हर तरह के बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। इसके तहत 15 से 18 साल की उम्र की लड़की और पुरुष के बीच कोई भी वैवाहिक संबंध शून्य होगा।

डर नहीं हिचकिचाहट थी, घाटी के हालात ही जुदा

नवीन नवाज, श्रीनगर

यहां राष्ट्रीय एकता शिविर में शांति, दोस्ती, भाईचारे और राष्ट्र भक्ति की बयार बह रही है। देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा वादी-ए-कश्मीर का असली रूप देख रहे हैं। ये कश्मीर की खूबसूरती और मेहमाननवाजी का कायल हो गए हैं।

लालचौक से करीब 22 किलोमीटर दूर श्रीनगर-लेह हाईवे पर गांदरबल स्थित फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में लगे शिविर का मकसद युवाओं में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को विकसित करते हुए उनमें एक-दूसरे की सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति समझ पैदा करना है। शिविर में असम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए 250 युवाओं में शामिल असम के डिब्रुगढ़ के उत्पल शर्मा ने कश्मीर में अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां आतंकवाद जैसी कोई बात है। हम सोच रहे थे कि कश्मीरी लड़के आतंकवाद

नया कश्मीर

गांदरबल में राष्ट्रीय एकता शिविर में लगा युवाओं का मेला

हर कोई कश्मीर की खूबसूरती और मेहमाननवाजी का कायल



जम्मू-कश्मीर में गांदरबल स्थित फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में कार्यक्रम प्रस्तुत करते युवा। शिविर में भाग लेने देश के विभिन्न हिस्सों से 250 युवा आए हैं।

मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हमारा सोचना गलत साबित हुआ। सभी शांति-सुरक्षा विश्वास और भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात करते हैं।

महाराष्ट्र से आए रोहित ने कहा कि जब परिवार को पता चला कि मैं कश्मीर में जा रहा हूं तो वह डर गए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया। यहां सिर्फ टंड ने परेशान किया है। सुबह हम यहां बाजार में गए थे, वहां कुछ दुकानदारों से बातचीत हुई, वे भी बदलाव से खुश हैं।

बाद में बात करते हैं,यह कहकर वह आगे बढ़ गया। सूरत गुजरात से आए विशाल वगानी ने कहा कि यहां की नेचुरल व्यूटी है, उसे देखकर मजा आता है। उससे ज्यादा अच्छा यहां के लोगों से मिलकर लगता है। मैं एक एनजीओ नवोदय यूथ क्लब का संचालक हूं। मैंने यहां बहुत से लोगों से बातचीत की है, मैं समझना चाहता था कि आखिर कश्मीर को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है। यहां कैप में कई कश्मीरी लड़कों से मैंने बातचीत की

तो उन्होंने कहा कि हमें तो आजादी ही पिछले साल मिली है। यहां लोग बहुत ही सहृदय हैं। वह यहां शांति, विकास और रोजगार की बात करते हैं।

कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है: दिल्ली के करोलबाग से आए 20 वर्षीय आकाशनंदन ने कहा कि कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने मां को सुबह फोन पर बताया कि यहां सब ठीक है तो वह मानने को तैयार नहीं थी। दिल्ली में जिस तरह से लोग सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर,

नागरिकता संशोधन कानून (सीए) को लेकर तनाव झेल रहे हैं, वैसे यहां कुछ नहीं है। बीती रात स्थानीय लड़कों से संवाद के दौरान मैंने यूं आतंकवाद, अनुच्छेद 370 और जिहाद की बात छेड़ दी तो उन्होंने कहा कि यह मुद्दे टीवी स्क्रीनो की बहस तक रहने दो। आम कश्मीरियों को कोई दिलचस्पी नहीं है। अख्तर ने कहा कि यह शिविर तो मिनी इंडिया है। हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन यहां हों ताकि पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लोग, हमारे हम उम्र नौजवान कश्मीर और हम कश्मीरियों की हकीकत को अच्छी तरह समझ सकें। यहां यह जो नौजवानों का मेला है, यह कश्मीर की हकीकत को बयान करने वाला है। कश्मीरियों के दिल में हमेशा दिल्ली है कश्मीरियों को पाक से जोड़ने वाले शायद नहीं जानते कि पाक तो कुछ साल पहले ही पैदा हुआ है। तारीख गवाह है कि कश्मीर और कश्मीरी सदियों से हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा रहे हैं।

चिदंबरम को जवाब के लिए मिला और समय



पी. चिदंबरम।

फाइल फोटो

जास, नई दिल्ली : 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल मैक्सिस डील मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे सांसद कांति चिदंबरम को जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने और समय दे दिया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गत 5 सितंबर को दोनों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ सुनवाई कर रही है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन ने आरोप कि चुनौती याचिका पर पीठ ने 11 अक्टूबर को नोटिस जारी कर जवाब मांग था, लेकिन अब तक जवाब नहीं दाखिल किया गया। वहीं चिदंबरम पिता-पुत्र की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता दयन कृष्णन व अर्षदीप सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की। इस पर पीठ ने तीन सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई 12 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यूज गैलरी

अब वन्यजीवों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा वेतन

बहराइच : वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) ने वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्द्धन व तत्करोों को सजा दिलाने के लिए अधिवक्ताओं को मासिक घनराशि देने का फैसला लिया है। अभी तक उन्हें पैरवी के लिए वन विभाग की ओर से प्रति केस 500 रुपये फीस मिलती थी। यह फीस भी उन्हें नकद भुगतान नहीं हो रही है, बल्कि बजट आने पर मुंहेया होती है। इससे पैरवी में अधिवक्ता रुचि नहीं लेते। अब उन्हें फीस के साथ ही 12 हजार रुपये मासिक पगार अलग से दी जाएगी। बहराइच के जिला वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि वन्यजीवों से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश व कोर्ट में चल रहे मामलों की मजबूत पैरवी कर सजा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। डीएफओ कर्तनियाघाट जीपी सिंह बताते हैं कि संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीवों के अपराध से जुड़े 90 मामले न्यायालय में चल रहे हैं। मामलों से जुड़े आरोपितों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। डब्ल्यूटीआई के कदम से इस प्रयास में और मजबूती मिलेगी। (जास)

इंदौर-पटना के बीच कल चलेगी विशेष ट्रेन, रिजर्वेशन आज से

इंदौर : पश्चिम रेलवे होली के अवसर पर इंदौर से पटना के बीच एक विशेष ट्रेन, विशेष किराए के साथ चलाएगा। होली पर लोगों को राहत देने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे के टाइम टेबल के मुताबिक, 09307 इंदौर-पटना स्पेशल ट्रेन छह मार्च को रात 11.30 बजे इंदौर से रवाना होगी और आठ मार्च को 2.50 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन 09308 पटना-इंदौर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। उक्त ट्रेन आठ मार्च की सुबह 5.50 बजे पटना से रवाना होगी और नौ मार्च को दोाहर 1.20 बजे इंदौर आएगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, थर्ड और सेकंड एसी श्रेणी के कोच होंगे। दोनों दिशाओं में यह स्पेशल ट्रेन देवास, उज्जैन, विदिशा, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनो पर ठहरेगी। ट्रेन के रिजर्वेशन गुरुवार से पब्लिक रिजर्वेशन काउंटरो और आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होंगे। (नईदुनिया)

जनमत मुद्दा

क्या भारत में लैंगिक समानता के लिहाज से महिलाओं की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

नवाब संपत्ति बंटवारा

28 मार्च को हो सकती है अंतिम बहस, फिर होगा बंटवारा, शर्मिला और सैफअली की तरफ से पक्ष रखने को तैमूर को दी पॉवर ऑफ अटार्नी

48 साल पुराने मामले में चार सप्ताह में आ सकता है फैसला

दीपक विश्वकर्मा, भोपाल

भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान की शहर और आसपास करीब 1500 एकड़ जमीन और पैलेसों के बंटवारे का फैसला चार सप्ताह में हो सकता है। 1972 से चले आ रहे नवाब संपत्ति विवाद के मामलों को मजूर कर दिया है। पूरा मामला अब अंतिम बहस के लिए लंबित है। 28 मार्च को अंतिम बहस होने के बाद मामले में फैसला हो सकता है। नवाब संपत्ति से जुड़ा प्रदेश का यह पहला मामला होगा, जिसमें संपत्ति के वारिसों को मालिकाना हक दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ना तो मामलों में कोई नई याचिका दायर की जा सकेगी और ना ही कोई दावा लगा सकेगा। अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। उधर, हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शर्मिला टैगोर व

सैफ अली खान की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सरदार तैमूर खान को पॉवर ऑफ अटार्नी दे दी है।

बता दें कि वर्तमान में 2700 करोड़ से अधिक की नवाब संपत्ति भौतिक रूप से शर्मिला टैगोर व सैफ अली खान के संरक्षण में है। इसका अधिकांश रिर्कोर्ड अहमदाबाद पैलेस, स्मॉल स्टॉफ हाउस, मोटर गैराज व रायसेन जिले के चिकलीद में था इसलिए अब इस रिर्कोर्ड को खुरद-बुरद करने की आशंका है। ताकि रिर्कोर्ड न मिलने की स्थिति में हिस्से ना हो पाए। अहमदाबाद पैलेस के सामने से विगत 18 फरवरी को नवाबकालीन दस्तावेजों से भरा जो ट्रक क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था वह सरदार तैमूर खान के अहमदाबाद पैलेस कोहेफिजा स्थित निवास के पास से ही पकड़ा गया था। लिहाजा एंटीक्युटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

सालेहा सुल्तान के चार पुत्रों को बनाया पार्टी

सरदार तैमूर खान नवाब हमीदुल्ला खान की तीसरी बेटी राबिया सुल्तान के बेटे अकबर हसन खान के पुत्र हैं। इसके अलावा साजिदा सुल्तान की सबसे बड़ी पुत्री सालेहा सुल्तान की मौत के बाद उनके चार पुत्र (अमेर, साद, उमर व फैज बिन जंग) को भी मामले में पार्टी बनाने का फैसला किया गया है। इनका रिर्कोर्ड भी अब संपत्ति पर अपना हक मांगने के लिए याचिका दायर की थी।इन दोनों मामलों में संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की जज अंजुली पालो ने दो मार्च को आदेश जारी किया। इसमें बिना किसी वजह के केस को लंबा ना खींचने के लिए कहा गया है।वहीं, चार सप्ताह में सभी मामलों की लिस्ट बनाकर अंतिम बहस कर फाइनल आर्डर सुनाने का फैसला सुनाया है।

शर्मिला टैगोर का नाम आयशा बेगम दर्ज

राबिया सुल्तान ने साजिदा सुल्तान की संपत्तियों पर अपना हक पेश करते हुए सन 2000 में संपत्ति के बंटवारे के लिए याचिका लगाई थी। इसी तरह नवाब हमीदुल्ला के बड़े भाई औबेदुल्ला खान की पत्नी बेगम सुरैया रसीद ने साजिदा सुल्तान के बाद आयशा बेगम (शर्मिला टैगोर) से नवाब संपत्ति पर अपना हक मांगने के लिए याचिका दायर की थी।इन दोनों मामलों में संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की जज अंजुली पालो ने दो मार्च को आदेश जारी किया। इसमें बिना किसी वजह के केस को लंबा ना खींचने के लिए कहा गया है।वहीं, चार सप्ताह में सभी मामलों की लिस्ट बनाकर अंतिम बहस कर फाइनल आर्डर सुनाने का फैसला सुनाया है।

सभी मामलों को किया मर्ज

1972 से अब तक पिछले 48 साल से नवाब संपत्ति में मालिकाना हक संबंधी करीब पांच से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं। सभी को मर्ज कर एक फाइनल बहस के लिए केस तैयार कर दिया गया है। नवाब संपत्ति में शामिल होटल इंटीरियल सेबरे जहां नवाबकालीन समय में स्टीफ व्हाटर्ड और टैनिंस कोर्ट हुआ करता था।

जम्मू में आइएसआइ का भारतीय जासूस गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू

पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एक एजेंट को नरवाल इलाके से दबोच लिया। आरोप है कि वह जम्मू, सांबा और कठुआ में सुरक्षा बलों के शिविरों के अलावा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में पुलों और नालों की तस्वीरें और वीडियो आइएसआइ को सोशल मीडिया के जरिए भेजता था। आरोपित पंकज शर्मा सांबा के तरोर का रहने वाला है। पुलिस उसके सोशल मीडिया एकाउंट को पुलिस खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित पंकज तीन वर्षों से पाकिस्तान में फोटो भेज रहा था। इसके बदले उसके सोशल मीडिया के एजेंट जम्मू कश्मीर के जवाबों से फर्जी नाम व पते से दोस्ती करते हैं। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वह किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। यदि कोई उन्हें अपने देश से जुड़ी जानकारी देने को कहता है तो उसकी शिकायत तुरंत साइबर पुलिस को करें।

था। उसके साथियों पर भी नजर रखी जा रही है। पता चला है कि वह सुरक्षा बलों की इमारतों, शिविरों, पुलों व नालों के वीडियों को खींच कर अपने ई-मेल अकाउंट के ड्राफ्ट में सेव कर देता था। उसकी ई-मेल का पासवर्ड आइएसआइ के अधिकारियों के पास भी था। जो पाक में बैठ कर उसकी ई-मेल खोल कर तस्वीरों व वीडियो को निकाल लेते थे और उनका प्रयोग कर भारत के विरुद्ध आतंकी हमलों की साजिश रचने में करते थे।

सोशल साइट में दोस्ती कर आइएसआइ ने फर्शाया : स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एसएसपी संदीप मेहता का कहना है कि आइएसआइ के एजेंट जम्मू कश्मीर के युवाओं से फर्जी नाम व पते से दोस्ती करते हैं। बाद में उन्हें लालच देकर जासूसी करवाते है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वह किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। यदि कोई उन्हें अपने देश से जुड़ी जानकारी देने को कहता है तो उसकी शिकायत तुरंत साइबर पुलिस को करें।

सोपोर में पुलिस चौकी के बाहर आतंकी हमला, एसपीओ शहीद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकियों ने एक पुलिस चौकी के बाहर पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया। इसमें एक एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर) शहीद व एक अन्य एसपीओ जखमी हो गया। हमले में एक स्थानीय दुकानदार की भी मौत हो गई। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चला रखा है।

सोपोर के वारपोरा इलाके में शाम को सूर्यास्त के बाद पुलिस और सीआरपीएफ का एक संयुक्त दल नियमित गश्त पर चौकी से निकल रहा था। चौकी से कुछ ही दूरी पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। इसमें दो एसपीओ और एक स्थानीय दुकानदार गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। गोलियों की आवाज से वहां हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद नागरिक अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी फायर करना चाहा, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संयम बरता। हमलावर आतंकियों ने इसका फायदा

गश्दी दल को बनाया निशाना, एक दुकानदार की भी मौत

भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी

बड़गाम में भी मुठभेड़, भाग निकले आतंकवादी

पुलिस और सेना के एक संयुक्त कार्यदल ने शाम करीब साढ़े पांच बजे बड़गाम के दुर्गौवारा में दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षाबलों को आते देख आतंकियों ने जवानों पर गोली चलाते हुए वहां से भागने का प्रयास किया। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। कुछ दूर मुठभेड़ के बाद आतंकियों की तरफ से गोलियां चलने की आवाज बंद हो गई। इस पर सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल की तलाशी ली तो उन्हें वहां कोई आतंकी नहीं मिला। सूत्रों की मानें तो दोनों आतंकी घेराबंदी तोड़कर भाग निकले।

उठाया और वह वहां से भाग निकले। इस बीच, एसपीओ वजाहत अहमद, एसपीओ शौकत खांडे और दुकानदार उमर सुबान वागे को सुरक्षाबलों ने तुरंत निक्टवॉर्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एसपीओ वजाहत और दुकानदार दोनों को मृत घोषित कर दिया।

देह व्यापार में गिरफ्तार टीएमसी नेता को जल्द मिलने वाला था राष्ट्रीय स्तर का पद

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के भोपाल में देह व्यापार के मामले में पकड़े गए तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिंह चौहान और अन्य नौ आरोपितों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि सचिन सिंह को जल्द ही टीएमसी में राष्ट्रीय स्तर का पद मिलने वाला था।

अब क्राइम ब्रांच ने भोपाल सीएमएचओ को पत्र लिखकर देह व्यापार की सरगना महिला डॉक्टर की जानकारी मांगी है। वहीं, एक पत्र कोलकाता टीएमसी के मुख्यालय भेजा है। इसके जरिये टीएमसी के नेता की जानकारी मांगी गई है।

गौरतलब है कि एक यूनानी क्लीनिक पर मंगलवार को क्राइम ब्रांच ने छापीमारी की थी। इस दौरान डॉक्टर महिला और उसकी तीन साथी, टीएमसी नेता समेत छह पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले थे। टीएमसी के नेता ने खुद को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बताया था। वह राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय है। करीब सात साल से वह टीएमसी से जुड़ा है। आरोपित ने कुबूल किया कि वह जल्द ही टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में शामिल होने वाला था। इससे उसे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जाने का मौका मिलता।

कसाब को पकड़ने वाले 14 पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति

मुंबई, प्रे़ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हमले के 12 साल बाद पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को दबोचने वाले 14 पुलिसकर्मियों को प्रोन्नत करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह घोषणा की। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नौ पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। देशमुख ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘सरकार ने 26/11 हमले के दौरान अजमल कसाब को पकड़ने वाले 14 पुलिसकर्मियों को एक रैंक प्रोन्नति देने का फैसला लिया है।’

26/11 के 12 वर्ष बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला

उन्होंने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को विभिन्न सम्मान दिए जा चुके हैं। अब उन्हें वर्तमान पद से आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति दी जाएगी। गौरतलब है कि 14 पुलिसकर्मियों की टीम गिरगाम चौपाटी पर सड़क जाम हटाने में जुटी थी। एक स्कोडा कार को टीम ने रोका जिसे इस्माइल खान चला रहा था और कसाब उसके बगल में बैठा था। मुठभेड़ में बाद पुलिस ने इस्माइल बातचीत में कुहवा, सरकार ने 26/11 हमले के दौरान अजमल कसाब को पकड़ने वाले 14 पुलिसकर्मियों को एक रैंक प्रोन्नति देने का फैसला लिया है।’

राष्ट्रपति ने निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका ठुकराई

नई दिल्ली, प्रे़ट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक पवन कुमार की दया याचिका ठुकरा दी है। वकील एपी सिंह ने सोमवार को पवन की ओर से दया याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही ठुकरा चुके हैं। अभी तक इस मामले के दोषियों को फांसी देने के लिए तीन बार डेथ वारंट जारी हो चुके हैं।

पैरामेडिकल की छात्रा ‘निर्भया’ के साथ दक्षिणी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जानलेवा हमला किया गया। बुरी तरह जख्मी पीड़िता ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। इस मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता,



पवन गुप्ता की फाइल फोटो।

राम सिंह और एक किशोर समेत कुल छह लोग दोषी करार दिए गए थे। राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली, जबकि किशोर सजा पूरी करने के बाद रिमांड होम से रिहा हो चुका है।

सेना भर्ती के मेडिकल मापदंड बदले

फिट आर्मी ► अभ्यर्थियों का भर्ती मैदान में होगा मेडिकल, अभिभावकों की बीमारियों का भी देना होगा ब्योरा

निशांत यादव, लखनऊ	
	
देश के समक्ष बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जोर-शोर से काम कर रही है। आधुनिक हथियारों से लेकर तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं। इन सबके बीच खासतौर से थल सेना में नई जान फूंकने के लिए पहले से अधिक फिट और पूरी तरह निरोगी अभ्यर्थियों को ही भर्ती में मौका देने की योजना भी बन गई है। इसके लिए एक अप्रैल से मेडिकल फिटनेस के मापदंड में व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। अभ्यर्थी ही नहीं, अब उनके माता-पिता की भी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाएगी।	
सेना में विपरीत हालात के बीच उन क्षेत्रों, खासकर जहां मेडिकल की सुविधा नहीं है, वहां जवान अक्सर तनाव में आ जाते हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए सेना के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व ने बीमारी और शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त जवानों पर चिंता जताई है। कहा गया कि ऐसे जवान न केवल संसाधनों को लेकर समस्या खड़ी करते हैं, बल्कि सैन्य ऑपरेशन के समय अपनी टीम के अन्य सदस्यों की जान भी जोखिम	

टैबलेट और कैप्सूल भी बनाते थे फर्जी दवा फैक्ट्री संचालक

संवाद सहयोगी, बर्दही	
	
हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला के बददी स्थित ग्लेनमाकं हेल्थकेयर फैक्ट्री के नाम से चल रहे नकली दवाइयों के कारोबार में नई बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी दोनों भाई यहाँ टैबलेट, कैप्सूल व सिरप सभी तरह की दवाइयां बनाते थे। इसका पता वहां मिली मशीनरी से लगा है। यह मशीनरी सभी तरह की दवाइयां बनाने में सक्षम हैं। आरोपित दोनों भाइयों के खिलाफ जांच चल रही है।	
फैक्ट्री मालिकों की ओर से फूड लाइसेंस लेकर अलग-अलग कंपनियों को दवाइयां बनाई जा रही थीं। आरोपित अनुराग शुक्ला व अभिनंद्र शुक्ला दोनों पांच वर्ष से इस काले कारोबार को चला रहे थे।	
राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय में इनके खिलाफ दो दिन पहले ही शिकायत आई थी। इस पर मंगलवार को विभाग ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इसके अपास 2016 में बना फूड लाइसेंस था। जहां यह फैक्ट्री लगी है, वहां औद्योगिक क्षेत्र न होकर ट्रांसपोर्ट तथा ट्रेडर्स के दुकानें हैं। उसकी आड़ में आरोपित लोगों की सेहत से बिगाड़ने वाली दवाइयों को	

नई किस्म	
	
चौगुनी होगी किसानों की आय, नारंगी रंग की होगी नई किस्म, बीएयू की खोज की देश के 11 संस्थानों में हो रही टेस्टिंग	
	
ललन तिवारी भागलपुर	
गर्मी के तीन महीनों अप्रैल, मई और जून में गंदे के फूल नहीं खिलते हैं। इसी दौरान शादी-विवाह, पूजन आदि में इसकी अधिक मांग होती है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (बीएयू) गंदे की नई किस्म विकसित कर रहा है। यह 42 डिग्री तापमान, यानी अब तक देश में सबसे अधिक गर्म मौसम में भी खिलेगा। अब तक बेंगलुरु, मद्रास और केरल में अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस पर गंदे के फूल खिल रहे हैं।	
जल्द रिलीज होगी नई किस्म : नारंगी रंग के गंदे की इस नई प्रजाति का देश के 11 बड़े संस्थानों में परीक्षण चल रहा है। परीक्षण के पूरा होने के बाद सरकार को हरी झंडी मिलते ही विश्वविद्यालय इसे रिलीज करेगा। बीएयू उद्यान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार बताते हैं कि फूलों की खेती करने वाले किसानों की आमदनी बड़े, इसी कारण इस नई किस्म का इजाद किया जा रहा है।	

जांच में नहीं हो पाई शराब की पुष्टि, पटना हाई कोर्ट ने दी 84 को जमानत

नए डेथ वारंट के लिए आज होगी सुनवाई	
जासं, नई दिल्ली : निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खारिज करने के कुछ देर बाद ही दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत में अर्जी दायर कर नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट ने इस पर चारों दोषियों को नोटिस जारी कर दिया। नया डेथ वारंट जारी करने के लिए गुरुवार को सुनवाई होगी। कुछ देर की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कहा कि अब चारों दोषियों के सभी उपाय पूरे हो चुके हैं। लिहाजा उनको नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि संविधान में जीने का अधिकार दिया गया है और दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। इसलिए दोषियों को नोटिस जारी किया जाता है और गुरुवार को उनका पक्ष सुना जाएगा।	

भारत घातक हमला करने में भी पारंगत : नरवाने

नई दिल्ली, एर्जेंसियां	
	
थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने का कहना है कि भारत परंपरागत युद्धकौशल में तो महारथ हासिल कर ही रहा है, वह पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) सीमाओं पर शक्तिशाली प्रहार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह प्रहार पूरी तरह से युद्ध न होकर उससे कुछ कम शक्तिशाली हमला होगा।	
जमीनी युद्ध पर आयोजित एक सेमिनार में बुधवार को सेना प्रमुख नरवाने ने कहा कि बालाकोट पर हवाई हमले करके हमने साबित कर दिया है कि अगर कोई युद्धकौशल में पारंगत हो तो हमला हमेशा युद्ध का रूप नहीं लेता है। सैन्य प्रचुरता को कई चरणों में स्थापित जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे बात युद्ध तक बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ब्लॉकचेन तकनीकों, लेजर और निर्देशित ऊर्जा हथियारों के संभावित प्रयोग के लिए प्रयासरत है।	

कुलदीप सेंगर पर दोष सिद्ध होते ही गांव में सन्नाटा

जागरण संवाददाता, उन्नाव	
	
माखी गांव की दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह उर्फ जयदीप और दो दारोगा सहित एक अन्य को दोषी करार दिए जाने का फैसला आते ही बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित माखी गांव में सन्नाटा पसर गया। विधायक के परिवारीजन और समर्थक फूट-फूटकर रो पड़े। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस भी सक्रिय हो गई। हर गली-चौराहे पर गश्त तेज कर दी गई। हालांकि, ग्रामीणों ने फैसले पर चुपपी साध ली है।	
पीड़िता के पिता से तीन अप्रैल 2018 को मारपीट हुई थी। पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ तमचा रखने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। आठ अप्रैल, 2018 को जेल में पीड़िता के पिता की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां आठ अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पीड़िता ने सजायापता पूर्व विधायक के भाई अतुल सिंह पर साथियों संग मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया था लेकिन, रसूख के आगे पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई एसआइटी जांच में अतुल और उसके साथियों के खिलाफ माखी का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की	

► दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में फैसला आते ही पूर्व विधायक के समर्थकों में छापी मायूसी

► माखी में बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट के निर्णय पर गांव के लोगों ने साधी चुप्पी

गई थी। सीबीआइ ने पूर्व विधायक को इसमें आरोपित नहीं किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसका नाम साजिश में शामिल कर लिया था। बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप, उसके भाई अतुल, दारोगा अशोक भदौरिया व केपी सिंह आदि को दोषी ठहराया। सजा का एलान 14 मार्च को होगा। फैसला आने के साथ ही पूर्व विधायक और पीड़िता के गांव माखी में सन्नाटा पसर गया। विधायक के परिवार और समर्थकों में मायूसी छापी थी।

सतक रहे पीड़िता के सुरक्षाकर्म : फैसला आने के बाद पीड़िता के घर पर मुस्तेद सीआरपीएफ के साथ ही पुलिस की सतर्कता भी बढ़ गई। गांव में गश्त कर पुलिस लोगों की प्रतिक्रिया जानती रही। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है।

पूर्व विधायक के आवासों पर खामोशी : फैसला आने के बाद पूर्व विधायक के माखी और उन्नाव शहर स्थित आवास में हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की

सुप्रीम कोर्ट का सज्जन कुमार को एम्स में जांच के लिए पेश करने का निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बीमारी के आधार पर जमानत मांग रहे 1984 के सिख विरोधी दंगे में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुवार को एम्स में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने का आदेश दिया है। सज्जन कुमार फिलहाल जेल में हैं, उन्हें दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कुमार ने बीमारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सज्जन कुमार के वकील और सरकार व अन्य वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि सज्जन कुमार को स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुवार को सुबह दस बजे एम्स में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड सैहत की जांच करने के बाद बताएगा कि सज्जन कुमार को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है कि नहीं है। और अगर है तो

1984 दंगा मामला

✎ खराब सेहत पर मांगी है जमानत, आज मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होंगे
✎ मेडिकल बोर्ड बताएगा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं

सज्जन को किस अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड साथ ही यह भी बताएगा कि कितने दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।
कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड को सज्जन कुमार को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत लगती है तो वह कारण दर्ज करके ऐसा कर सकता है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले पर कोर्ट एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगा।
इससे पहले, सज्जन कुमार के वकील विकास सिंह ने खराब सैहत का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की मांग की।

दुष्कर्म मामले में नित्यानंद की हाजिरी सुनिश्चित करे अदालत

		
		
सुप्रीम कोर्ट।	फाइल	

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के रामनगर जिले की निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह 2010 के तकनीकी सैन्य युद्ध का मुखिया साबित कर दिया है।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आतंकी संगठन आइएस अमेरिका, ब्रिटेन से आगे से सैन्य प्रमुख एमएम नरवाने ने कहा कि आतंकी संगठन आइएस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में अमेरिका और ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है। इराक और सीरिया में जो आतंकी संगठन आइएस 17वीं शताब्दी की सोच और कार्यशैली में डूबा है, वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में 21वीं सदी के थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि इनमें कुछ भी ऐसा गंभीर नहीं है जिसमें आतंकीयों

कसेगा शिकंजा
► सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की रामनगर अदालत को दिया निर्देश
► नित्यानंद के पूर्व ड्राइवर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द

जारी किया था। पीठ ने कहा कि संबंधित निचली अदालत को सुनवाई के लिए आरोपित नित्यानंद की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले महीने नित्यानंद की जमानत रद्द कर दी थी। तब राज्य पुलिस ने बताया कि नित्यानंद धार्मिक यात्रा पर है।

नित्यानंद दुष्कर्म के साथ ही अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपित है। उसे 22 अप्रैल, 2010 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसी साल 11 जून को उसे जमानत मिल गई थी। उसके बाद से वह फरार हो गया। पिछले दिनों खबर आई थी कि नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर कैलाशा नाम से अपना देश बसा लिया है।

बहुत सताया इन लोगों ने, कड़ी सजा पर मिलेगा सुकून : पीड़िता

जागरण संवाददाता, उन्नाव : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से पूर्व विधायक और उसके भाई को दोषी ठहराए जाने पर दुष्कर्म पीड़िता ने संतोष जताया। उसने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि उसे सुकून तब मिलेगा, जब पिता की हत्या के मामले में दोषियों को अधिकतम कड़ी सजा मिलेगी और जुर्माना होगा। पीड़िता ने कहा कि पूर्व विधायक, उसके भाई व समर्थक लगातार मेरे परिवार का उल्टीड़न करते रहे हैं। पिता को बेहमरी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे साथ दुष्कर्म किया गया चाचा को झूठे मुकदमों में जेल भिजवाया गया। अब न्यायालय ने न्याय देना शुरू किया है। अब सरकार से मांग करेंगे कि चाचा पर लगे झूठे मुकदमे भी वापस लिए जाएं।

पूर्व विधायक पति कुलदीप सिंह सेंगर और देवर अतुल सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सिंह गहरे सदमे में हैं। न्यायालय का निर्णय आने के बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय से उम्मीद नहीं टूटी है। तीस हजारी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। उनका कहना है कि कोर्ट की अंतिम चौखट तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

जाली नोट बरामदगी प्रकरण में बिहार में एनआइए का छाप

जागरण संवाददाता, मधुबनी	
	
बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोटगांव में बुधवार सुबह एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने जाली नोट बरामदगी प्रकरण में छापेमारी की। बिहार पुलिस के सहयोग से मो. मुमताज के घर और उसके आस-पड़ोस के घरों में कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी में एनआइए के डीएसपी समेत आधा दर्जन पदाधिकारी मौजूद थे। घर में रखे पांच मोबाइल एनआइए द्वारा जब्त किए जाने की सूचना है। हालांकि इस संबंध में एनआइए की टीम व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे। बताते चलें कि इससे पूर्व भी मो. मुमताज के घर दो बार केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीम छापेमारी कर चुकी है। दिसंबर 2019 के पहले सप्ताह में पूर्णिया बस स्टैंड के पास डीआरआइ	

की टीम ने एक लाख 90 हजार 500 रुपये के जाली नोट के साथ मो. मुमताज को गिरफ्तार किया था। वह मधुबनी का रहने वाला है। चर्चा यह भी है कि बरामद जाली नोट पाकिस्तान में छपे होने को लेकर एजेंसी गहरे पड़ताल कर रही है।



दैनिक जागरण

विपति में भी एक अवसर छिपा होता है

दिल्ली दंगों पर चर्चा

दिल्ली दंगों को लेकर संसद में तीसरे दिन भी हंगामा होने पर हैरानी नहीं। संसद में अब ऐसा ही अधिक होता है। राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर भी संसद में अब सार्थक चर्चा के बजाय हंगामा करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। इससे भी खराब बात यह है कि जैसा हल्ला-हंगामा लोकसभा में होता है वैसा ही राज्यसभा में भी। बीते कुछ समय से तो यह देखने को मिल रहा है कि लोकसभा से अधिक हंगामा राज्यसभा में होता है। यह विडंबना ही है कि जिस सदन से यह अपेक्षित है कि वह कहीं अधिक धीर-गंभीर होकर चर्चा होकर करेगा वहां अब ऐसा कम ही होता है। दिल्ली दंगों पर संसद में चर्चा होनी ही चाहिए और दलगत हितों से ऊपर उठकर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इसके आसार दूर-दूर तक नहीं और इसका प्रमाण है संसद में वैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी। शाब्द विपक्ष के इसी रवैये के कारण सत्तापक्ष यह चाह रहा है कि दिल्ली दंगों पर चर्चा होली के बाद हो। उसकी यह आशंका निराधार नहीं कि इस चर्चा के दौरान कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शांत होते माहौल पर विपरीत असर डालें, लेकिन उसे इस चर्चा से बचते हुए भी नहीं दिखना चाहिए। बेहतर होगा कि सत्तापक्ष और विपक्ष चर्चा के समय के साथ ही इस पर भी एकमत हों कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए? अभी तक का अनुभव यही रहा है कि अच्छा-खासा समय यह तय करने में खप जाता है कि चर्चा किस नियम के तहत हो?

यदि दिल्ली दंगों पर चर्चा के दौरान केवल आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होता है तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस चर्चा में वे तथ्य सामने आना आवश्यक हैं जिनके चलते दिल्ली का माहौल बिगड़ा और वह भीषण दंगों से दो-चार हुई। चूंकि इन दंगों में जान-माल की व्यापक क्षति होने के साथ ही देश का नाम खराब हुआ है इसलिए कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। बीते तीन दिनों में संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि सरकार और पुलिस की लापरवाही से दंगा हुआ। इसमें दोराय नहीं कि सरकार समय रहते हालात नहीं भांप सकी और दिल्ली पुलिस अपेक्षित तत्परता नहीं दिखा सकी, लेकिन इसी के साथ यह भी सही है कि विपक्षी दलों ने आग लगाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। विपक्षी दलों के साथ तथाकथित सविल सोसायटी के तमाम लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केवल जहर ही नहीं उगला, बल्कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने की हर संभव कोशिश की। विपक्ष के हंगामा मचाने से उसकी आग लगाने वाली यह राजनीति छिपने वाली नहीं है।

सख्त सजा के सबक

दुमका में छह वर्षीय बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने वाले बच्ची के रिश्ते के चाचा समेत तीन दोषी युवकों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। चार दिन में इस मामले की सुनवाई पूरी कर दुमका की पोक्सो कोर्ट ने पूरे देश के सामने नजीर पेश की है। यह लोमहर्षक घटना इसी साल 5 फरवरी को हुई थी। महज 22 दिन में कोर्ट में आरोप गठन किया गया। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। तीन दिन तक दिन-रात सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को फांसी की सजा सुना दी। यह मामला अब पूरे देश में नजीर बन चुका है। पुलिस और फॉरेंसिक लैब के विशेषज्ञों ने भी तीव्र गति से अपना काम किया। इस मामले में तेज कार्रवाई का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सात फरवरी को बच्ची का शव बरामद होने के बाद मामले की एफआइआर दर्ज करते ही मुख्य आरोपित की तलाश में पुलिस ने पूरी ताकत लगाते हुए 11 फरवरी को मुंबई में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी ही निशानदेही पर अन्य दो आरोपितों को भी पकड़कर 12 फरवरी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत में 26

फरवरी को इस मामले का आरोप पत्र दाखिल हुआ और 27 फरवरी को अदालत में आरोप गठित हुआ। वहीं दिन-रात सुनवाई कर तीन दिनों में गवाही भी पूरी कर ली गई। खास बात यह भी थी कि दुमका के पाँक्सो कोर्ट में तीन दिन तक सिर्फ इसी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। मंगलवार को दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही यह फैसला कानून के इतिहास में दर्ज हो गया है। इससे कड़ा संदेश भी गया कि दुष्कर्म लाख कोशिश कर लें, मगर वे बचेंगे नहीं। न्यायालय में पुख्ता सुबूतों के साथ अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर प्रतिशोध लेना ही चुस्ती दिखाई वह भी समाज के लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। समाज को भी इस तरह के अपराध के प्रति सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हुए बेटियों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने से लेकर उनकी नैतिकता और चरित्र का स्तर ऊपर उठाने के लिए हर प्रयास करने चाहिए।

दुमका दुष्कर्म मामले में दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस की चुस्ती और अदालत की तेजी सलाम करने लायक है। यह सिलसिला बना रहे



प्रदीप सिंह

कांग्रेस का क्या होगा, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कांग्रेस के लोगों को पहले तय करना पड़ेगा कि गांधी परिवार का क्या होगा?

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों दो संघर्षों में उलझी हुई है। दोनों समानांतर स्तर पर चल रहे हैं। पहला संघर्ष कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने का है। दूसरा, कांग्रेस के प्रथम परिवार यानी नेहरू-गांधी परिवार का स्तबा कायम रखने या कहिए कि वीडो बनाए रखने का है। दोनों के केंद्र में सोनिया गांधी हैं। बहुत से कांग्रेसी 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत को सोनिया का कि चमत्कार मानते हैं। उन्हें उम्मीद है फिर चमत्कार होगा, पर सोनिया गांधी का एक ही लक्ष्य है, राहुल को रिलांच करना। समस्या यह है कि रिलांच के लिए न तो नया कलेवर है और न ही तेवर। कहावत है, रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। कांग्रेसियों का नेहरू-गांधी परिवार के साथ रिश्ता कुछ ऐसा ही हो गया है, पर पिछले कुछ दिनों से बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं। जिस कांग्रेस में परिवार के खिलाफ बोलना कुफ्र समझा जाता था उसमें परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, दबी जवान से ही सही। पार्टी का एक वर्ग परिवार के म्यूजिकल चेयर के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। परिवार को पहला झटका यही लगा कि कांग्रेसजनों ने इस फैसले को इस तरह स्वीकार किया जैसे इसी का इंतजार कर रहे हों। लंबी कसरत के बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया और वे सहर्ष बन भी गईं। पार्टी की बागडोर परिवार के ही हाथ में ही रह गई। अब राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने को तैयार भी हैं और नहीं भी। सोनिया गांधी राहुल के अलावा किसी और को अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाहतीं। राहुल ने सबको भला बुरा कहकर अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, लेकिन सवाल यह है कि

संदीप दीक्षित, अभिषेक मनु सिंघवी मिलिंद देवड़ा, शशि थरूर, मनीष तिवारी,

सलमान सोज और संजय झा जैसे कई नेता अलग-अलग ढंग से नेतृत्व, विचारधारा, धर्मनिपेक्षता, राष्ट्रवाद, आर्थिक नीति जैसे मुद्दों पर स्पष्टता, संगठन में फैसले के तरीके, विकेंद्रीकरण और कार्य संस्कृति को मुद्दा उठा रहे हैं। इनमें से कई नेताओं ने यह भी संकेत किया है कि पार्टी में पुराने नेता बदलाव नहीं होने दे रहे। जो बदलाव की बात कर रहे हैं उनके सामने भी कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है। वे बस चाहते हैं कि यथास्थिति बदले। जैसे चल रहा है वैसे नहीं चल सकता। इन नेताओं को भी अब यह लगने लगा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन पहले परिवार में सत्ता के बंटवारे की गुथी तो सुलझे। राहुल गांधी ने करीब आठ महीने पहले यह कहकर अध्यक्ष पद छोड़ दिया था कि परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। परिवार को पहला झटका यही लगा कि कांग्रेसजनों ने इस फैसले को इस तरह स्वीकार किया जैसे इसी का इंतजार कर रहे हों। लंबी कसरत के बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया और वे सहर्ष बन भी गईं। पार्टी की बागडोर परिवार के ही हाथ में ही रह गई। अब राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने को तैयार भी हैं और नहीं भी। सोनिया गांधी राहुल के अलावा किसी और को अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाहतीं। राहुल ने सबको भला बुरा कहकर अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, लेकिन सवाल यह है कि

समस्याएं पैदा करता सोशल मीडिया

सोशल मीडिया नए जमाने का सच है। आप सर्जक हों, जैसे लेखक, मीडियाकर्मी, राजनेता या मार्केटिंग के उस्ताद या फिर सूचना और मनोरंजन के शाहक-उपभोक्ता, दोनों को इसकी अलग-अलग वजहों से जरूरत है। सर्जक और उपभोक्ता की जरूरतों के ये दोनों छोर रोजाना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के मंचों के जरिये अरबों-खरबों सूचनाओं और छवियों आदि से लबरेज रहते हैं। इन जरूरतों ने हमें सोशल मीडिया में इतना गायिल कर रखा है कि हमें इनके बिना एक पल का चैन मिलना मुमकिन नहीं लगता। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट के बाद तमाम कयासों के साथ एक सवाल भी उछला कि क्या सोशल मीडिया अफवाहों और नकारात्मक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का जरिया बनकर रह गया है? शायद यह इंसान की जन्मजात कमजोरी है कि वह सच पर यकीन जरा दे से करता है। इसके उलट झूठ की उड़ान उसे तुरंत ही रोमांचित करने लगती है। हालांकि जब तक मामला किस्सागोई किस्म की गप्पबाजी तक रहता है तब तक ठीक रहता है। वक्त काटने का यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। आखिर सामाजिक जुड़ाव के ये तौर-तरीके ही तो हमारी सोसायटी को एक हद तक इंसानी बनाते हैं, लेकिन बीते करीब एक-सवा दशक में सोशल मीडिया के आ जाने के यह कला तमाम विकृतियों का शिकार हो गई है। फेसबुक और ट्विटर जैसे जितने भी इंतजाम सामाजिक जुड़ाव के नाम पर किए गए, आखिर में जाकर वे झूठ को पंख देने के काम आते भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहों को विस्तार देने का जो आरोप लगा, वह फिजूल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक फायदे उठाने से लेकर उत्पादों के नाम पर सिर्फ सपने बेचने का एक पूरा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इससे कायम हुआ है।

अफवाह और झूठ के इस तंत्र को जांचने की एक अहम कोशिश दो साल पहले मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डाटा विश्लेषकों ने की थी। वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि अफवाहों, झूठी और फर्जी खबरों में जंगल की आग की तरह बेइतहा तेजी से फैलने की भरपूर ताकत होती है। फेक न्यूज के सिलसिले कहां, क्यों और कैसे बनने शुरू होते हैं और कहाँ जाकर खत्म होते हैं, इसे 2006 से 2016 के

बीच 10 वर्षों में 30 लाख लोगों द्वारा सिर्फ ट्विटर पर प्रेषित की गई सूचनाओं (टवीट्स) में मौजूद झूठ की पड़ताल से परखा गया। विज्ञान जर्नल-साइंस में छपे एक लेख के मुताबिक यह पड़ताल डाटा विश्लेषकों को इस निष्कर्ष पर ले गई कि ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और प्लेटफॉर्म-इनसे फर्जी खबरें तेजी से और बहुत दूर तक फैलती हैं। सच उनके मुकाबले में कहीं टिक नहीं पाता है। कुछेक मिसालें भी इस बारे में दी गईं। जैसे एक उदाहरण यह बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक बीमार बच्चे की मदद को अपना निजी विमान भेज दिया तो इस सच्ची खबर को रीट्वीट करने वालों



की तादाद महज 1300 थी, लेकिन जब एक खबर यह आई कि ट्रंप के एक रिश्तेदार ने मौत से पहले की गई अपनी वसीयत में लिखा कि ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए तो फेक न्यूज होने के बावजूद यह सूचना 38 हजार लोगों के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट

की गई। सच्चाई यह थी कि ट्रंप का ऐसा कोई रिश्तेदार ही नहीं था और खबर पूरी तरह फेक थी।

यहां अहम सवाल यह है कि आखिर लोग सच बात को उतनी तेजी से फॉरवर्ड क्यों नहीं करते जैसे कि फेक न्यूज को। एक बड़ी वजह यह नजर आती है कि भरोसेमंद सूचना या खबर में फर्जी खबरों की तुलना में सनसनी का स्वेग नहीं होता। जिससे रीट्वीट होने और बड़े दायरे तक पहुंचने के मामले में फेक न्यूज सच्ची और असली खबरों पर भारी पड़ती है। भरोसेमंद स्रोत, विश्वसनीय व्यक्ति (पत्रकार आदि) के माफत आई सूचना एक बार में हजार से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती और आगे भी उसके प्रसार की गति मंद पड़ती जाती है। इसके बरक्स अविश्वसनीय स्रोत और अश्वकचरी सूचनाओं से लैस व्यक्ति के जरिये आई फेक न्यूज छोटे-छोटे दायरों में शेयर होते हुए आगे बढ़ती है, वक्त बीतने के साथ रफ्तार पकड़ती है और अधिकतर मामलों में सच्ची खबर को पीछे छोड़कर उससे कई गुना अधिक आगे निकल जाती है। ऐसे में कइ ऐसे मौकों पर, जब पूरे माहौल में ही जहर भरा हो तो झूठ का एक कतरा भी ऐसे सोशल मंचों पर आग लगा देता है और हालात संभाले जाने से पहले उसकी लपटें अनगिनत लोगों को झुलसा देती हैं।

हालांकि टीवी-अखबार आदि से जुड़े पत्रकार तमाम वेबसाइटों की मदद से सूचना का नीर-क्षीर विवेकी विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन यह काम अभी बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चाहे खुद को सोशल मीडिया से अलग करने का फैसला हो या फेक न्यूज फैलाने वाले सोशल मीडिया के लाखों अकाउंट बंद करना हो, फिलहाल यह यकीन हमारे दिलों में पैदा होना मुश्किल है कि आने वाले वक्त में भी सूचनाओं के नकलीपन की कलाई महज ब्यू टिक या लाल-नारंगी निशानों की पहचान स्थापित करने भर से खुल जाएगी। हालात में किसी सुधार की उम्मीद सिर्फ इससे है कि वे लोग जो सोशल मीडिया पर झूठ का कारोबार करते हैं, पकड़े जाने और सजा पाने के भय पर खुद ऐसी हरकतों से बाज आएंगे। बेहतर दुनिया बनाने के लिए जरूरी है कि झूठ के ये नकाब उतारे जाएं।

(लेखक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं) response@jagran.com



अवधेश राजपूत

क्या बोलकर लौटें? पुरानी रवायत तो यह है कि कांग्रेसी रोएं, गिड़गिड़ाएं कि आइए-हुजूर बचाइए, पर यहां तो कोई बुला ही नहीं रहा। राहुल लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा भी नहीं लग रहा। कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की दुनिया से परिवार का पहली बार वास्ता पड़ा है।

प्रियंका गांधी का खेमा अलग जोर लगाए हुए है कि भाई नहीं तो बहन। अंदरखाने की खबरें यह भी हैं कि प्रियंका राज्यसभा में जाना चाहती हैं, पर सोनिया भेजना नहीं चाहतीं। जो भी हो, कांग्रेसी जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल के बारे में क्या तय किया और फिर राहुल ने उनके तय किए पर क्या तय किया? प्रियंका तय नहीं कर पा रहीं या अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई हैं कि अपने बारे में तय कर सकें। सवाल यह भी है कि उनके बारे में कौन तय करेगा-मां या भाई? इस पूरे प्रसंग में कहीं कांग्रेस कार्यसमिति या अखिल भारतीय कांग्रेस

कमेटी का कोई जिक्र नहीं आता। यह हाल है देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो सुबह-शाम जनतंत्र बचाने की गुहार लगाती है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि पचमढ़ी जैसे मंथन शिखर होने चाहिए, जिसमें विचार हो कि भाजपा से अलग कांग्रेस राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करे? अभी तो यहां परिवार के सदस्यों की भूमिका पर घर में ही मंथन का दौर पूरा नहीं हो रहा।

कांग्रेस की हालत 2004 से 2013 के बीच की भाजपा जैसी हो गई है। दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व जगह खाली करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यथास्थिति टूटने से कई लोग असुरक्षित महसूस करते। यह जानते हुए कि देश में मोदी लहर चल रही है, उन्हें स्वीकार करने को नेतृत्व तैयार न था। इस पर जनता ने कैडर पर दबाव डाला और कैडर ने नेताओं पर। इसके बावजूद आखिरी पल तक मोदी को रोकने की

कोशिश हुई। कांग्रेस के मामले में तो जनता मुंह घुमाकर खड़ी है और कैडर परिवार से ऊब चुका है। जो बात देश को काफी समय से दिख रही थी और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी दिखने लगी है वह परिवार के लोगों को नहीं दिख रही। इस पर दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है- तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं

पिछले छह साल में गांधी परिवार के लोगों के कामकाज के तरीके या सोच कोई बदलाव नहीं आया है। सोनिया गांधी से जिनको बहुत उम्मीद है वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। आखिरी बार उन्होंने किस चुनाव में खुलकर प्रचार किया था, यह याद करना कठिन है। राहुल गांधी की हालत नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली है। कभी-कभी तो उनके मामले में अढ़ाई कोस भी ज्यादा लगता है। प्रियंका गांधी को राजनीति एक शगल की तरह नजर आती है। कभी मोटर साइकिल पर कभी स्टीमर पर चलकर कहीं पहुंच जाना उन्हें क्रांति की तरह लगता है। राजनीति उतारके बस थी कचला भी नहीं लगी। परिवार के नाम पर मिलने वाला डिविडेंड अब बंद हो गया है। यह बात उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद भी उनके समझ में नहीं आई। कांग्रेस का क्या होगा, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कांग्रेस के लोगों को पहले तय करना पड़ेगा कि इस परिवार का क्या होगा? परिवार बचने के लिए सवाल भी नहीं रहा और हटने को भी तैयार नहीं है। लाख टके का सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यही तो पूछा था, संदीप दीक्षित ने। यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं) response@jagran.com



ऊर्जा

भक्त

भगवान का अपने सच्चे भक्तों से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। गीता में प्रभु कहते हैं, "भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में"। भारत की पुण्यभूमि पर तो ऐसे अनेकों भक्त संत हुए जिन्होंने अपनी निश्चल भक्ति के बल पर भगवान से सहज आत्मीय संबंध कायम किया। आदि शंकराचार्य, विद्यापति, मीरा, रामकृष्ण परमहंस, वामनधर चट्टोपाध्याय (बामा ध्याय) और न जाने कितने ही ऐसे संत हुए। शंकराचार्य को भगवान शिव का साक्षात अवतार माना जाता है, जिन्होंने मात्र सात वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने सभी शस्त्रों का अध्ययन कर लिया और 16 वर्ष की अवस्था में सी से भी अधिक ग्रंथों की रचना कर दी। महज 32 साल की आयु में अपना शरीर त्याग देने से पहले उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से देश के चारों कोनों में चार मठ स्थापित कर दिए थे। विद्यापति की भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवान उनके घर एक चाकर के रूप में रहे थे। मीरा के लिए तो प्रभु ने उनके विष को स्वयं पी लिया। रामकृष्ण परमहंस को भगवती पुत्रवत स्नेह देती थीं। उनके बुलाने पर दौड़ी चली आती थीं। बामा खेपा रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। मां भगवती के तारा रूप के वह इतने करीब कि स्वयं को उनके सम्मुख पूर्णरूपेण बालक ही समझते थे। अगर कभी मां तारा उनकी प्रार्थना नहीं सुनतीं तो वह बच्चों की भांति रोना-पीटना आरंभ कर देते थे। कहा जाता है कि माता तारा ने उनका जूठा भी खाया था। वास्तव्य भाव से बामा खेपा को दूध पिलाती मां तारा की कहानी से कौन परिचित नहीं है। इनकी यहां रखने का आशय इतना ही है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, हमें प्रभु को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि निराशा के गहनतम अधरों में भी वह हमारे इर्द-गिर्द ही होते हैं। हमें बस पुत्रभाव से अपने हाथ बढ़ाने हैं और वह उसे थाम लेंगे।

चंदन कर्ण

ही बताएगा। फिलहाल तो एक बात ही कही जा सकती है। देर आए, दुरुस्त आए।

हिटेंद्र डेड़ा, चिल्ला गांव

खुफिया चूक भी रही

दैनिक जागरण के 3 मार्च के अंक में प्रकाशित संपादकीय, दंगों पर सियासी दंगल, में बताया है कि दिल्ली में दंगा किसी धार्मिक मसले पर नहीं, बल्कि सीएफ़ रूपी राजनीतिक मसले पर हुआ। लेकिन इन दंगों में जो जाने गई हैं, उसकी भरपाई दशकों तक पीड़ित परिवर्जनों के लिए नहीं हो पाएगी। सरकारी और निजी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है वह भी निंदनीय है। इस तरह के दंगों को प्रायोजित आतंकवाद की श्रेणी में रखकर ही कड़े कानूनों के तहत लाना चाहिए। अब राजधानी के माहौल को काबू में बनाए रखने की जरूरत है। थोड़ी कसर गुप्तचर सेवाओं से भी रह गई थी कि उन्हें समय रहते किसी अनहोनी की सूचना नहीं मिल पाई, अन्यथा दंगे फसाद इतने बड़े स्तर पर नहीं होते।

युगल किशोर शर्मा, खान्वा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल: mailbox@jagran.com

कीटनाशकों का बढ़ता प्रकोप

रेणु जैन

कीटनाशकों के कुप्रभाव को लेकर समय-समय पर खबरें आती रहती हैं। अभी तक तो यह माना जाता था कि कीटनाशक फसलों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, मगर अब तथ्य सामने आया है कि इनके उपयोग से कुषकों की भी जान जाने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन को लेकर एक नया विधेयक लाने का फैसला लिया है। इसमें नकली या खराब गुणवत्ता के कीटनाशकों की बिक्री और उत्पादन गैरकानूनी होगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले को एक पांच साल तक जेल और अधिकतम 50 लाख रुपये का जुर्माना होगा। इतना ही नहीं यदि इस तरह के कीटनाशकों से फसलों को भी नुकसान पहुंचा तो मुआवजा भी कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों से ही वसूला जाएगा। विव्ध बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 25 लाख लोग हर वर्ष कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के शिकार होते हैं, उनमें से करीब पांच लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। कहा तो यहां तक

दुनिया में 25 लाख लोग हर वर्ष कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के शिकार होते हैं, उनमें से पांच लाख काल के गाल में समा जाते हैं

जाता है कि भारत में कीटनाशक दवाओं का व्यवसाय लगभग 224 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ग्रीनपीस संस्था द्वारा पंजाब में वर्ष 2010 में चलाए गए जीवित माटी अभियान के तहत किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला था कि पंजाब में रसायनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पिछले चालीस वर्षों में भंडिंडा में शूरिया के उपयोग में 750 फीसद तक की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि कीटनाशक नकली हुए तो उनसे किसानों की जान को भी खतरा होता है, क्योंकि किसान तथा खेतिहर मजदूर पीठ पर पंपिंग स्प्रे लगाकर खुले बदन काम करते हैं। कई खेतिहर मजदूर दो-दो पाली में काम करते हैं। वे सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखते, जबकि पूरा बदन ढंका और मुंह पर मास्क लगा होना आवश्यक है।

चश्मा भी ऐसा होना चाहिए, जो आंखों को चारों ओर से ढंक दे। हाथ में दस्ताने पहनना तो निहायत जरूरी है। कई बार उपकरणों में लीकेज होता है। ऐसे में कीटनाशक उपकरण से बाहर टपकते रहते हैं जो घातक हो सकता है। कीटनाशक के छिड़काव के लिए हवा के रुख का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा बचे हुए कीटनाशक के डिब्बे एवं पैकेट को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। कीटनाशकों के खाली डिब्बे किसी अन्य काम में नहीं लेने चाहिए। उन्हें नष्ट कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। कीटनाशक छिड़कने के बाद खेत में किसी मनुष्य या जानवर को एक तय समय तक नहीं जाने देना चाहिए। ये जानकारीयां कृषि सहायक अधिकारियों को हर किसान को देनी चाहिए। किसान इतने पढ़े-लिखे भी नहीं होते कि वे पैकेटों पर लिखी सब सूचनाएं समझ सकें। वैसे भी पैकेट पर इतने छोटे अक्षरों में नियम, चेतावनी, किन्ता रसायन किन्ती मात्रा में मिला होना लिखा होता है कि उन्हें पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। (लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मूल समस्या की अनदेखी

दिल्ली दंगों के सबक शीघ्र से लिखा गया प्रकाश सिंह का लेख पढ़ा। लेखक ने दिल्ली दंगों को हालिया विधानसभा चुनावों में विभिन्न दलों के नेताओं के 'हेट स्पीच' से जोड़ा है, लेकिन यह तो समस्या का अति सरलीकरण हुआ। आश्चर्य है कि लेखक ने दिल्ली के दंगों पर बात करते समय विगत दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में ही नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, जामिया सहित कई इलाकों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। वास्तव में दिल्ली में किसी बड़ी अनहोनी के बीज तो तभी पड़ गए थे, जिसे खाद-पानी देने का काम किया उक्त कानून के संबंध में अल्पज्ञानी और राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकने वाले नेताओं तथा तथाकथित बुद्धिजीवियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने। कानून के विरोधियों के द्वारा व्यस्त सड़कों को जाम किए जाने, उनको दहला यदा-कदा मजहबी और विद्वेषपूर्ण नारों को लगाए जाने तथा अतिक्रमित सड़कों को खाली कराने में प्रशासन और न्यायपालिका की नाकामी से स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई। लेखक ने आगे अपने लेख में बिगड़ते माहौल का हवाला देकर यह राय दी है कि नागरिकता संशोधन कानून पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी जाए। यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत एक संभ्रभु राष्ट्र है, जिसे विशुद्ध मानवीय आधार पर एक कानून का निर्माण किया है। इस पर सिर्फ इस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि कतिपय इस्लामिक देशों तथा कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई

मेलबाक्स

है। भारत सरकार उनके साथ कानून के प्रावधानों के संबंध में चर्चा कर उन्हें आश्वस्त कर सकती है। यदि वह कश्मीर पर अपने ताजा कानूनी बदलावों के संबंध में यूरोपीय देशों के सांसदों को विश्वास में ले सकती है तो इस मामले में भी ऐसा कर ही सकती है। नि:संदेह सरकार को इस कानून पर पूरे निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

kumar9470@gmail.com

देर आए, दुरुस्त आए

अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में हुए शांति समझौते की ताजा पहल सराहनीय है। पूरी दुनिया को इसका स्वागत करना चाहिए। महाभारत में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति अनमोल है इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। शांति जैसे भी स्थापित होती हो कर लेनी चाहिए। अमेरिका और तालिबान के बीच ये संघर्ष लगभग पिछले दो दशकों से चलता आ रहा था। जारी आकड़ों के अनुसार इस खुनी खेल में अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकवाद और हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। शांति की पहल का एकमात्र जरिया बातचीत ही है। इस समझौते से अमेरिकी फौज को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही अफगानिस्तान की अवाम के जीवन में भी अमन चैन कायम होगा। अमेरिका और तालिबान के बीच ये समझौता बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वैसे इस समझौते पर दोनों पक्ष कितने खरे उतरते हैं ये तो वक्त

आजकल

अशोक श्रीवास्तव

वरिष्ठ टीवी पत्रकार



ईरान में हुए हालिया चुनावों में कट्टरपंथियों को बड़ी जीत मिली है। कुल 290 में से 230 सीटों पर कट्टरपंथियों की जीत हुई। सबसे बड़े सूबे तेहरान में तो सभी 30 सीटें कट्टरपंथियों ने कब्जा ली हैं, जबकि 2016 के नतीजे इसके उलट थे, यानी उस वक़्त तेहरान की सभी 30 सीटें उदारवादियों ने जीती थीं। ईरान के चुनावों की खास बात ये थी कि इन चुनावों में कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने वाले दो भागों में बंटे हुए थे। एक तरफ कट्टरपंथी थे तो दूसरी तरफ उदारवादी। राष्ट्रपति हसन रुहानी उदारवादियों की तरफ झुके मध्यमार्गी नेता हैं जो 2013 में उदारवादियों के समर्थन से ही चुनाव जीते थे। वर्ष 2017 में भी उन्हें भारी समर्थन मिला और वो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति हसन रुहानी ने पिछले साल ही जुलाई में परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद से ही उदारवादी और कट्टरपंथी दोनों कैंपों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। कट्टरपंथी, राष्ट्रपति रुहानी की विदेश नीति और ईरान में राजनीतिक सुधारों का विरोध कर रहे थे और उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई का समर्थन मिल रहा था। फिर इसी साल अमेरिकी हवाई हमले में ईरान की कुर्द फौस के प्रमुख जेनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने भी देश में कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत होने का मौका भी दे दिया और बहाना भी। इन सब हालात में हुए चुनावों में उदारवादियों का हथ्र यह हुआ है कि वो महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, जबकि पिछली संसद में उनकी गिनती 120 की थी। तो अब ईरान की नई संसद का चेहरा पिछली संसद से पूरी तरह बदला-बदला छेला जाएगा। निवर्तमान संसद के 20 प्रतिशत से भी कम सांसद नई संसद में दिखाई देंगे। जब कट्टरपंथियों को इतनी बड़ी जीत मिली है तो ईरान की राजनीति और उसकी कूटनीति में कट्टरपंथियों का दबदबा दिखाई देना स्वाभाविक है। यानी अब ईरान पूरी तरह कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है। इससे राष्ट्रपति रुहानी की मुश्किलें बढ़नी थीं तब हैं और भविष्य में ईरान में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे।

कट्टरपंथ बनाम कट्टरपंथ : आखिर ईरान की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? क्या ईरान के लोगों ने उदारवादियों को नकार दिया है? हालांकि चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा

ईरान में कट्टरपंथियों की वापसी

दिल्ली के दंगों पर ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने जो बयान दिया उससे शायद कुछ लोगों को हैरानी हुई होगी, क्योंकि ईरान भारत का पुराना मित्र है । आखिर इतने पुराने और मजबूत रिश्तों को नजरअंदाज करके जवाद जरीफ ने क्यों दंगों को ‘ भारतीय मुसलमानों के खिलाफ संगठित हिंसा ’ कह कर सीधे- सीधे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया ? पर हैरान होने की जरूरत नहीं । दरअसल फरवरी के आखिरी सप्ताह में ईरान में हुए संसदीय चुनाव के जो नतीजे आए हैं, यह उसी की परिणति है । हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत अली चेगेनी को तलब किया और ईरान को दो टूक कहा है कि वह भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे । बावजूद इसके भविष्य में ऐसा फिर से नहीं होगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ईरान के चुनाव में वही हुआ जिसकी आशंका थी



ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ।

फाइल फोटो

सकता कि ईरान के लोगों ने उदारवादियों को ठुकरा दिया है। दरअसल आयतुल्ला खामनेई को सीधे रिपोर्ट करने वाली 12 सदस्यों की गार्डियन काउंसिल ने जिस तरह उदारवादी खेमों के सात हजार से ज्यादा उम्मीदवारों की दावेदारी खारिज कर दी थी उसके बाद से ही माना जा रहा था कि चुनाव तो कट्टरपंथी ही जीतेंगे। कुल 15 हजार लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया था। इन्में से 7,296 लोगों को अयोग्य करार दिया गया, तो गार्डियन काउंसिल के इस कदम से 31 प्रांतों की 290 सीटों के चुनाव में ज्यादातर सीटों पर कट्टरपंथी नेताओं के मुकाबले में कट्टरपंथी नेता ही थे।

वैसे तो ईरान की कट्टरपंथी मजहबी संस्था गार्डियन काउंसिल हमेशा से ही नेताओं पर इसी तरह लगाम कसे रहती है और देश की ‘मजहबी लाइन’ से अलग राय रखने वाले नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन इस बार खास बात यह रही कि गार्डियन काउंसिल ने ऐसे लोगों को भी संसदीय चुनावों में उतरने नहीं दिया जो पिछले चुनावों में काउंसिल की ‘लक्ष्मण रेखा’ लांघ कर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लगभग 80 सांसदों को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। इसके चलते उदारवादी धड़ों ने चुनावों में कोई दिलचस्पी ही नहीं ली। इराना ही नहीं, 31 में से 22 प्रांतों में उदारवादियों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन तक नहीं किया।

काफी कम रहा मतदान प्रतिशत**:** उदारवादी नेताओं को चुनावों से दूर रखने के फैसले ने ईरान के निराशा में पिरे लोगों को और नाउम्मीद कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि ज्यादातर लोग चुनावों में वोट देने के लिए घरों से निकले ही नहीं, 41 साल के इस्लामिक रिपब्लिक

ऑफ ईरान के इतिहास में इस बार सबसे कम यानी 42.57 फीसद मतदान हुआ। तेहरान में तो सबसे कम 26.2 फीसद मतदान हुआ, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने लोगों से कहा था कि वोट देना उनका धार्मिक कर्तव्य है। लेकिन जब उनकी अपील पर भी लोग मतदान के लिए नहीं निकले तो उन्होंने कहा कि दुश्मनों के दुष्प्रचार और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के कारण लोग वोटिंग के लिए नहीं निकले। 2016 के पिछले चुनावों में लगभग 61.83 प्रतिशत मतदान हुआ था और 2012 में तो 66 फीसद मतदान हुआ था।

इस बार कम मतदान होने के कारण भी हैं। ऐसे लोगों की तादात बढ़ी है जिन्हें लगता है कि वोट देने से कुछ नहीं बदलेगा। राष्ट्रपति रुहानी से लोगों को जिस खुलेपन और बदलाव की अपेक्षा थी वो पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान में बेरोजगारी की दर जो 2018 में 14.5 फीसद थी, 2019 में यह बढ़कर 16.8 फीसद हो गई है। लगातार प्रतिबंध झेलने के कारण जीडीपी गिर रही है। आइएमएफ ने 2020 के लिए ईरान में शून्य विकास दर रहने का अनुमान जताया है। नवंबर में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिए जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। यहां तक कि प्रदर्शनाकारियों को नियंत्रित करने के लिए गोली चलानी पड़ी जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई। ऐसे हालात में लोगों को चुनाव से कोई उम्मीद नहीं थी।

राष्ट्रपति चुनावों पर असर की आशंका : इन नतीजों का असर 2021 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर भी पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अब राष्ट्रपति रुहानी के लिए संसद से तालमेल बनाना ही नहीं, 41 साल के इस्लामिक रिपब्लिक

अमेरिका-तालिबान समझौते का जटिल पेच

पुणर्रजन

अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच आतंकी गुट तालिबान के बीच शांति समझौता हो गया है। इस समझौते का विश्व के कूटनीतिक हलकों में इसलिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति, डॉनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ समझौता किए जाने की सहमति जताई थी, तब से दुनिया जानना चाहती थी कि अमेरिका आखिर तालिबान को किस तरह से नियंत्रित करेगी? इस समझौते से न तो अफगानिस्तान की सरकार खुश है और ना ही पाकिस्तान का सत्ता तंत्र। सवाल है कि आखिर इस समझौते का हथ्र क्या होगा? राष्ट्रपति गनी इससे मना कर रहे हैं कि उन्होंने पांच हजार तालिबान बंदियों को रिहा करने का कोई वादा किया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि तीन तालिबान बंदी, जो काबुल के पास बगराम कारा में रखे गए हैं, उन्हें सशर्त छोड़ने पर बात हुई थी। इन तीन तालिबानों में दो को अंतरराष्ट्रीय सहयोगी बल ने पकड़ा था।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बीते 18 वर्षों में अफगानिस्तान में 2,450 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। इस समय सबसे अधिक पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। उसकी वजह दोहा शांति समझौते के कुछ बिंदु हैं, जिससे यह संदेश गया है कि शाह महमूद कुरेशी देश की संप्रभुता, अमेरिका के यहां गिरवी रख आए हैं। समझौते के एक अनुबंध में लिखा है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच किसी विवाद को अमेरिकी मध्यस्थता के जरिये सुलझाया जाएगा। सवाल यह है कि दोहा घोषणापत्र के जिस खंड को लेकर आज पाकिस्तान बिफर रहा है, उसके विदेश मंत्री तब क्या होश में नहीं थे? दोहा में इस समझौते के साक्षी स्वयं शाह महमूद कुरेशी रहे हैं। पाकिस्तान पहले से इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया कि उसके द्वारा सरपस्त अतिवादी अफगानिस्तान में विस्फोट करते रहे हैं। इसे लेकर काबुल और इस्लामाबाद में कई बार तनाव हुआ है।

इस बातचीत में तालिबान ने नेता मुल्ला अब्दुल गनी बारादर को पाकिस्तान ने बतौर ट्रंप काई इस्तेमाल

किया था। 24 अक्टूबर 2018 को तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बारादर को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया था। वह आठ वर्षों से पाकिस्तान की कस्टडी में थे, जिनके माध्यम से तालिबान नेतृत्व को बातचीत के लिए राजी कराया गया था। सवाल यह है कि अमेरिकी-नाटो फौज की वापसी, और अफगानिस्तान में चुनाव के बाद क्या उस इलाके की भू-राजनीतिक स्थिति वैसी ही रहेगी, जैसी आज है? क्या उसका दुष्प्रभाव आने वाले दिनों में कश्मीर पर नहीं पड़ना है? यह ठीक है कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तक अपनी भूमिका को सीमित कर रखा है, बावजूद इसके काबुल स्थित भारतीय दूतावास बराबर अतिवादियों के निशाने पर रहा है। चाबहार बंदरगाह से मध्य एशिया तक पहुंचने का जो मार्ग हम तैयार कर रहे हैं, वह अफगानिस्तान में शांति के बिना अधूरा सा है। तालिबान की वापसी के बाद, नई परिस्थितियां और चुनौतीपूर्ण होंगी, इसे नकारा नहीं जा सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जो खबरें आ रही हैं वो भी चिंता बढ़ाने वाली हैं। शायद यही कारण रहा कि ईरान के चुनावों की चर्चा मीडिया में कम हुई और यह चर्चा ज्यादा हुई कि चीन के बाद वो कोरोना से प्रभावित दूसरा बड़ा देश बन गया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में यह तर्ज भी कसा कि ईरान के चुनावों में कोरोना वायरस की जीत हुई है।

ट्वीट-ट्वीट

हर्ष मंदर कहते हैं कि भारत के भविष्य का फैसला न तो संसद करेगी और न ही सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सड़कों पर उतरी भीड़ करेगी। असल में भारत के दुश्मन घर में ही बैठे हुए हैं।

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

भारत में कोरोना के दूध मामले क्या सामने आए लोग मास्क खरीदने आए बिच बेचने ही गए। हमारे देश में रोजाना करीब 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, और बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बावजूद हेल्मेट के लिए ऐसी बेवैनी नहीं दिखती। वाहे वायरस हो या सड़क हादसे, सब जगह सुशुभा सर्वोपरि होनी चाहिए।

पंकज नयन आइपीएस@jpspankajnain

अमेरिका खासकर टेक्सास में प्राइमरी चुनाव की प्रक्रिया में अनियमितताओं की बातें सुनने में आई हैं कि लोगों को वहां पर वोट डालने के लिए पांच-पांच घंटे तक कतार में रहना पड़ा। अमेरिका में चुनाव के बारे में यह सब सुनने के बाद मैं अपने देश यानी भारतीय चुनाव आयोग और समूची प्रक्रिया को सलाम करता हूं खासतौर से इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे यहां अमेरिका से कई गुना अधिक मतदाता हैं।

प्रणय रॉय@PrannoyRoyNDTV

मोदी राज में शांतिपूर्ण इलाके भी अशांत हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्र की नीतियों के कारण गतिशील, बंद और कर्फ्यू से मुक्ति और विकास के लिए शांति-सद्भाव चाहिए।

सीताराम येचुरी@SitaramYechury



नवनीत शर्मा

राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश



सोख लेना, लेकिन दवा में नमी बरकरार रखना। लेकिन जहर ही सही, मीठा था, इसलिए उचित कच्चा माल मिला या नहीं, यह सोचने का वक़्त किसी के पास नहीं था। ऑर्डर आया होगा कि इतना माल चाहिए और दवा की जगह जहर बना दिया गया। दवा के नमूने मानकों पर हार गए। मामला दर्ज हो गया है, अब अगला कदम गिरफ्तारी ही होगा। कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उत्पादन तो 17 फरवरी से ही बंद है।

किसका नुक़सान हुआ? जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में 12 घर सूने हुए, बस यही? एक ही घर की दहलीज का दीपक बुझने पर जब सन्नाटा चिंचाड़ता है, उसे कोई संवेदनशील झेल सकता है? जहर दिलाया कंपनी डिजिटल इंडिया की पीने वाली दवा को कोल्डबेस्ट में यही डाला गया था। बेशक, इसमें प्रोपेलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल होना था। प्रोपेलीन को खूबी यह है कि इसे आमतौर पर खाने में सुरक्षित समझा जाता है। इसका काम है दवा का अतिरिक्त पानी



सबसे बड़े फार्मा हब कहे जाते हिमाचल की व्यवस्था के खिलाफ गंभीर शिकायत है। यह उस परिपाटी में दी गई ढील का नतीजा है जहां नियम माने जाएं तो गलती की संभावना नहीं रहती। यह हिमाचल प्रदेश में कतिपय दवा उद्योगों के लालच और उसकी निगरानी की स्वाभाविक कमी का दुष्परिणाम है। इस सबमें हिमाचल ने भी अपनी प्रतिष्ठा को दाग लगवाया है। अगर 500 से अधिक दवा उद्योगों की निगरानी घर प्रतिक ही नहीं, नए जम्मू-कश्मीर की प्रतिवा का हिस्सा नहीं होगा, यह भरोसे के संकट का प्रश्न है, यह एशिया के

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक उन्नति में दवा उद्योग की भूमिका से इन्कार नहीं है, लेकिन सूचनाएं बहुत कुछ कहती हैं। सरकार को अपना अमला मजबूत करना चाहिए। सिर्फ हर बार यह देना काफी नहीं है, 'चिकित्सक जेनरिक दवाइयां लिखें।' वे दवाइयां किन हालात में, किस मंशा और जानकारी के साथ बन रही हैं, इन तक नज़र हो सरकार की। अन्यथा, ब्रांड बनने की राह पर चला हिमाचल कमजोर रह जाएगा। छवि का सूचकांक गिराने के लिए जम्मू-कश्मीर जैसी एक ही घटना बहुत बड़ी है। जेनरिक दवाइयां के आग्रह

में क्या उचित कच्चे माल की जगह मीठा जहर इस्तेमाल होने देंगे? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन समय-समय पर मानक पूरे न करने वाली दवाओं के बारे में चेतावनी जारी करता है। बीते वर्षों में उक्त कंपनी का नाम भी बार-बार आया है, सवाल यह है कि क्या उस बैच और लॉट की सारी दवाइयां वापस बुलाई जाती हैं? सदैव इसलिए होता है, क्योंकि अगर विभाग के पास लोग ही नहीं हैं, तो यह सब निगरानी कौन करता है? ताजा घटना यह है कि चंद्रनगर कानुनपुर के दो भाई भी बड़ी में दवाओं का कारखाना संचालित कर रहे थे। इनके पास लाइसेंस फूड का था, लेकिन दवाइयां बन रही थीं। इनकी अंग्रेजी दवाइयों पर जिन कंपनियों का नाम दर्शाया जा रहा था, उन्हें भी जानकारी नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। जाहिर है, इसमें भी हिमाचल की बदनामी हो रही थी। सिलसिला कई माह लिए जम्मू-कश्मीर जैसी एक ही घटना बहुत बड़ी है। जेनरिक दवाइयां के आग्रह

भंडाफोड़ तो हुआ। प्रचलन यह है कि बड़ी कंपनी को जब निश्चित अवधि में सामान तैयार कर भेजना होता है, वह अपना काम किसी छोटी कंपनी को सौंप देती है। लेबल, बैच, लॉट सब पहली कंपनी के होते हैं। उससे भी काम न संपले तो दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को काम सौंप देती है। इसी प्रक्रिया में मानक ध्वस्त होते हैं। प्रोपेलीन ग्लाइकोल के स्थान पर डाई एथेलीन ग्लाइकोल आ जाता है। इसी प्रकार की और गलतियां होती हैं। इसी प्रक्रिया में ऐसी कंपनियां भी उग आती हैं जो दो कमरों में चलती हैं जिनके पास फूड लाइसेंस पर ही दवा बनाने का कानिूल हुनर होता है। ऐसे तत्वों पर नकेल कसने की जरूरत है क्योंकि बात जिंदगी की है। जिंदगी ऐसी शय है जो मांते के आखिरी द्वीप तक तैरना नहीं छोड़ती। बीमारी में तो दवा पर ही भरोसा होता है। नक्श लायलपुरी ने यू ही नहीं कहा था : जहर देता है कोई, कोई दवा देता है जो भी मिलता है मेरा दर्द बढ़ा देता है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में सक्षम है?

54.20

हां

36.90

नहीं

8.90

कह नहीं सकते

आज का सवाल

क्या सोशल मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री की पहल महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दिल्ली दंगा पर्यटन खूब रहा फल- फूल, बड़े- बड़े नेता वहां रहे आजकल झूल। रहे आजकल झूल साथ में लेकर लश्कर, भले वहां के लोग कह रहे बस कर- बस कर। रहे बने जो लोग अभी तक भीगी बिल्ली, बढ़िया मौसम देख घूमने निकले दिल्ली!

- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

डॉ. प्रतीक माहेश्वरी

असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरिन ट्रेड, नई दिल्ली

एक पुरानी कहावत है कि 'बोलने वाले की छाछ भी बिक जाती है और ना बोलने वाले का घी भी पड़ा रह जाता है।' यह बात मार्केटिंग और उसके महत्व को बेहद आसान तरीके से समझाती है। किसी भी व्यवसाय की सफलता काफी हद तक प्रभावी मार्केटिंग पर भी निर्भर करती है। मौजूदा बेहद गतिशील और जटिल चुनौतियों से भरे हुए व्यावसायिक परिवेश एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता ने मार्केटिंग को हर व्यवसाय का अपरिहार्य अंग बना दिया है।

मार्केटिंग के स्वरूप में बदलाव : मार्केटिंग की शुरुआत किसी न किसी रूप में व्यवसाय के विकास के साथ ही रही है, परंतु समय के साथ इसका स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है। अध्ययन और शोध की दृष्टि से एक विषय के रूप में विपणन का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। शुरुआती दिनों

संभल कर हो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

समय के साथ व्यापार और बाजार का मिजाज बदलता है । व्यावसायिक परिदृश्य में आज सस्टेनेबल मार्केटिंग को व्यापक स्तर पर अपनाने की जरूरत है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन युक्ति संगत तरीके से किया जा सके

में इसे उत्पादन से जोड़कर देखा गया जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना था। बीती सदी के पांचवें दशक तक विपणन को लेकर यही धारणा बनी रही कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है। बाद में इसको उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी विशेषताएं, डिजाइन और विश्वसनीयता से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसे ‘उत्पाद अवधारणा’ यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के रूप में जाना गया। फिर एक दौर ऐसा आया जब पूरा ध्यान सिर्फ उत्पाद को बेचने और उसके प्रचार प्रसार पर रहा। इसे ‘विक्रय अवधारणा’ यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट के रूप में जाना गया। इस दौरान कंपनियों के लिए ग्राहकों की जरूरतों, चाहतों और सार्थक ग्राहक जुड़ाव से अधिक महत्वपूर्ण उत्पाद की अधिकारिक बिक्री थी।

पिछली सदी के आठवें दशक के बाद मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का ध्यान ग्राहक की जरूरतों और चाहतों की ओर केंद्रित होने लगा एवं व्यवसाय के केंद्र में ग्राहक

को सर्वोपरि माना जाने लगा। इस दौर में मार्केटिंग का प्रमुख उद्देश्य वैल्यू डिलीवरी से जुड़ा रहा। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद मार्केटिंग का स्वरूप उपभोक्ता तथा सामाजिक कल्याण की ओर उन्मुख हुआ जिसे ‘सामाजिक या समग्र विपणन’ यानी सोशिएटल या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में जाना गया। इस विचार ने मार्केटिंग की अवधारणा में सामाजिक चिंता को शामिल करने पर जोर डाला। दूसरे शब्दों में कहें तो उपभोक्ता की जरूरतों और चाहतों को पूरा करते समय कंपनियों को

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनकी व्यावसायिक गतिविधियां उपभोक्ता और समाज के लिए हानिकारक न हो। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान स्थापित मार्केटिंग की सोच और मान्यताएं आज के समय में पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं हैं। उस दौर में प्राकृतिक संसाधन इतने अधिक मात्रा में थे कि वे असीमित प्रतीत होते थे। औद्योगिक कचरे को नष्ट की पर्यावरण की क्षमता भी व्यापक थी। अतः व्यापार का काम स्पष्ट रूप से प्राकृतिक संसाधनों का

दोहन करते हुए यथासंभव तेजी और कुशलता से उत्पादों में परिवर्तित करना था। लेकिन इससे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का तेजी से क्षय हुआ है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन भी असीम नहीं हैं यानी उनकी भी एक सीमा है, और कई मामलों में तो उनकी आपूर्ति बेहद कम है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की रिसाइकलिंग, जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव आदि आज बड़ी वैश्विक चुनौतियां बनती जा रही हैं। इन सबके चलते व्यापार का परंपरिक प्रतिमान यानी मॉडल मौजूद परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। और इसी वजह से मार्केटिंग के जानकारों का रझान एक नए स्वरूप, नई अवधारणा की ओर होने लगा है जो स्थायित्व की बात करता है। इसी अवधारणा को ‘सस्टेनेबल मार्केटिंग’ या सतत विपणन कहा जाता है।

पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता से संदर्भ : सस्टेनेबल मार्केटिंग को

खरी-खरी

शांति भइया, आओ शांतिपाठ करें

मुकेश जोशी

मेरे घर उस दिन मेहमान आए थे, इसलिए मैं उनके लिए रोटी-पानी के इंतजाम में उलझा था, उनके स्वागत में ‘ट्रंपेट’ बजा रहा था, मंगलगाan और बधाये गवा रहा था। मुझे क्या पता कि पड़ोसी के छोरों ने ‘अमंगल’ की तैयारी कर ली थी। मैं ‘भव्य स्वागत’ में मशगूल था, उन्होंने ‘भव्य हिंसा कार्यक्रम’ कर डाला।

अब मेहमान जा चुके हैं और मेरा मन भीतरई दुःखी है। किससे बात करूं, किससे शिकायत करूं, किसके सामने रोना रोऊं? सोचता हूं मेरे दोस्त शांतिालालजी कल ही रिटायर हुए हैं, उन्हीं के साथ बैठकर दो-टप्पी बात कर लेता हूं। सरल-सहज शांति भइया मेरी सब बात सुनकर दुखी हो गए। उनकी पीड़ा देख मैं फिर बोला- यार, इस देश में आदमी तो मरने के लिए पैदा हुआ है, वो किसी दंगाई की गोली से मरे, हार्टअटैक से या एसिड अटैक से, पर भाई लोगों ने गाड़ियां क्यों जला दीं? गाड़ियां तो धर्म्मनिरपेक्ष होती हैं ना? वे न तो ललाट पर तिलक लगाती हैं, न पहिए में कलगावा बांधती हैं, न तो उनकी दाढ़ी उगती है और न ही वे पथराव करती हैं। और तो और, वे अपने दस्तावेज दिखाने से भी कभी यह कहकर मुकरती नहीं कि ‘हम कागज नहीं दिखाएंगे।’

भाईचारे से याद आया कि इसका संधि विच्छेद बहुत बुरा होता है- ‘भाई’ और ‘चारा’। मतलब भाई को चारा बनाकर खा जाओ। स्कूलों में तो कभी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया, फिर ये कौन-सी ‘किताब’ में लिखा है कि भाई को चारा बना लो? कल्लोगारद की ये बात सुनकर शांति भइया का दुख और गहरा हो गया। उनका मन हल्ला करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ हलकट टाइप के लोगों के बारे में बात करूंगा तो शायद उनका मन हल्का हो जाए। तब मैंने माइक लेकर मंडराते गिटों की बात शुरू की, जो बाग से निकली आंच पर अपने-अपने सांच संकेर रहे थे।

ये गिटु भी कमाल के धर्म्मनिरपेक्ष थे, उन्हीं लाशों पर बैठ रहे थे, जो इनकी ‘भूषव’ शांत कर रही थी। बुद्धिजीवी गिटों ने अपने-अपने इलाके, माइक और स्टूडियो संचाल लिए थे।

इतनी सारी बातें करने पर भी शांति भइया का दुख कम नहीं हुआ। सोचता हूं अब ‘शांतिपाठ’ ही एकमात्र विकल्प बचा है।

Copyright © 2020 Jagran Media Pvt. Ltd. All rights reserved.

चार दिन भी नहीं चला अमेरिका और तालिबान का समझौता

तालिबान के हमले में अफगान सेना और पुलिस के 20 जवानों की मौत, जवाब में अमेरिका ने आतंकियों के ठिकानों पर बोला हमला

काबुल, एएफ़ी : अफगानिस्तान में स्थायी शांति बहाली के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ समझौता चार दिन भी नहीं चला। आतंकी संगठन तालिबान ने मंगलवार रात कुंडुज और उरुजगान जिले में हमला कर अफगान सेना और पुलिस के 20 जवानों की मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ ही घंटों बाद आतंकी संगठन ने इस वारदात को अंजाम दिया। जबकि ट्रंप ने बरादर से हुई बातचीत को काफी अच्छा बताया था। बौखलाए अमेरिका ने बुधवार को दक्षिण हेलमंद प्रांत में आतंकी संगठन के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए।

अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के प्रवक्ता सनी लोरेट ने एक ट्वीट में कहा, ‘हवाई हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं ताकि हमलों को रोक़ा जा



कुंदुज प्रांत में अफगान नेशनल आर्मी के चेकपोस्ट पर तालिबान के हमले के बाद जवान पूरी चौकसी बत रहे हैं।

क्या था समझौता

अफगानिस्तान में स्थायी शांति लाने के लिए बीते शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान ने एक समझौते पर दस्तख़त किए थे। इसके तहत अमेरिका को 130 दिनों के अंदर अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या 13 हजार से घटाकर 8,600 करनी है। अमेरिका ने 14 महीनों में अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने पर भी सहमति व्यक्त की है। समझौते में कहा गया है कि 10 मार्च को नार्थ में होने वाली बातचीत से पहले अफगान सरकार अपने 1000 कैदियों के बदले जेल में बंद पांच हजार आतंकियों को छोड़ेगी। लेकिन राष्ट्रपति अशराफ गनी ने वार्ता से पहले आतंकियों को छोड़ने से इन्कार कर दिया है।

सके। पिछले 11 दिनों में अमेरिका की ओर से यह पहला हमला है। तालिबान नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वादा

किया था कि वे हिंसा कम करेंगे और हमले नहीं बढ़ाएंगे। हम तालिबान से अपील करते हैं कि वे हमले बंद करें और

अपने वादे पूरे करें। हम पहले ही कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपने सहयोगी की मदद करेंगे। हम क्षेत्र में शांति

स्थापना को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारे ऊपर अफगान सेना की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान और अमेरिका समझौते का पालन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि तालिबान लोगों की शांति की इच्छा को अनदेखी कर रहा है।’ सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों ने मंगलवार को हेलमंद की चौकियों पर 43 हमले किए थे।

कुंदुज और उरुजगान में तालिबान का बड़ा हमला : प्रांतीय परिषद के सदस्य सफ़ीउल्ला अमीरी के अनुसार, तालिबान ने कुंडुज के इमाम साहिब जिले में तीन सैन्य चौकियों पर हमला किया। इसमें दस सैनिकों और चार पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इसके अलावा तालिबान ने उरुजगान प्रांत में पुलिस पर बड़ा हमला बोला। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता जराई इबादी ने कहा, दुर्भाग्य से इस हमले में छह पुलिसवाले मारे गए और सात घायल हो गए।

कोरोना की चपेट में आए ईरान के सभी प्रांत

महामारी का कहर ▶ वायरस से 92 की हो चुकी है मौत, संक्रमित लोगों की संख्या 2900 पार

राष्ट्रपति रुहानी बोले, अमेरिका मदद करना चाहता है तो दवाओं से प्रतिबंध हटाए

दुबई, एर्जेसिया : ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने बुधवार को कहा कि मुल्क के सभी प्रांत कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। उन्होंने देश की जनता को परेशान नहीं होने का आशवासन भी दिया। अब तक ईरान में वायरस की चपेट में आकर 92 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 2,922 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सऊदी अरब ने मक्का में आने वाले तीर्थयात्रियों पर रोक लगा दी है। यह रोक स्थानीय नागरिकों पर भी होगी। प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इस बीच, विश्व बैंक ने गरीब देशों की मदद के लिए 12 बिलियन डॉलर (करीब 84 हजार करोड़ रुपये) सहायता पैकेज का एलान किया है। चीन में 38 और मौत के बाद कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 2981 हो गई है। चीन में संक्रमण के 80,270 मामले सामने आ चुके हैं। दुनियाभर में अभी तक 3100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 91 हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं। रुहानी ने कैबिनेट बैठक के दौरान



ईरान में कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ डर का माहौल है। राजधानी तेहरान की इस तस्वीर में एक कर्मचारी ऑफिस की लिफ्ट के बटन को अंगुली की बजाए लकड़ी की तीली से दबा रहा है।

एएफ़पी

कहा, ‘यह महामारी तेजी से फैल रही है। वायरस देश के सभी प्रांतों में पहुंच गया है। यह सही मायने में एक वैश्विक बीमारी है।’ राष्ट्रपति ने कहा, हम इस पर जल्द ही नियंत्रण कर लेंगे। अमेरिकी पेशकश पर बिना नाम लिए रुहानी ने कहा, ‘वह झूठी संवेदना जता रहे हैं। अगर वह वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो दवाओं पर लगा प्रतिबंध हटा लें।’ पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पेंपियो ने महामारी से निपटने के लिए सहायता की पेशकश

की थी। अब तक ईरान में कई सरकारी अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के चलते एक अफसर की मौत भी हो चुकी है। पड़ोसी देश इराक में भी कोरोना वायरस से 70 वर्षीय धर्मोपदेशक की मौत हो गई। द. कोरिया में रेड अलर्ट, इटली में स्कूल-कालेज बंद : द. कोरिया में 142 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही देश में वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 5328 हो गई है। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया

भारतीय छात्र की मौत के मामले में ऑस्ट्रेलियाई महिला को जेल

मेलबर्न, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसे में भारतीय छात्र जतिंदर बरार की मौत के मामले में 27 वर्षीय स्थानीय महिला सोफी लुईस को बुधवार को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। सोफी कोरी की गई कार को नशे की हालत में तेज रफ़्तार से चला रही थी, जिसकी चपेट में भारतीय छात्र आ गया था। यह हादसा पिछले साल चार जनवरी को हुआ था।

एडिलेड की जिला अदालत के जज जोआन ट्रेसी ने सोफी को सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि जेल से ब्रूटने के बाद भी सोफी की ड्राइविंग पर रोक रहेगी। पुलिस अभियोजक ने एक चश्मदीद के हवाले से कोर्ट को बताया था कि हादसे के वक्त कार करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चल रही थी। सोफी ने माना था कि वह पिछले साल चार जनवरी को एडिलेड के उपनगर सेलिसबरी में तेज गति से कार चला रही थी। इसी दौरान उसने 25 साल के जतिंदर को टक्कर मार दी थी। बरार एकार्डेंटिंग की पढ़ाई के साथ ही सुपरमार्केट में डिलिवरी ट्रक ड्राइवर की नौकरी भी करता था। हादसे के बाद सोफी कार समेत भाग निकली थी।

इदलिब में सीरिया और तुर्की के सैनिक आमने–सामने

अंकारा, एपी : तुर्की के आक्रामक रुख से सीरिया का इदलिब प्रांत अब युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है। यहां पर सीरिया की रूस समर्थित सरकारी सेना तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही गुटों से भिड़ गई है। तुर्की ने लड़ाई को अपने पक्ष में करने के लिए वहां पर हजारों सैनिक भेजे हैं लेकिन हालात फिलहाल उसके नियंत्रण से बाहर हैं। रूस ने कहा है कि कई स्थानों पर विद्रोहियों को पीछे कर तुर्की की सेना आगे आ गई है और वह सीधे सीरिया की फौज से भिड़ रही है। अशांति के इस माहौल में तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दौगन गुरुवार को मॉस्को पहुंचकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और टकराव खत्म करने की कोशिश करेंगे।

तुर्की ने कहा है कि बुधवार को हुए संघर्ष में सीरियाई सेना के हमले में उसके दो और सैनिक मारे गए हैं और छह घायल हुए हैं। तुर्की सीमा से सटे सीरिया के इदलिब प्रांत में पिछले नौ साल से विद्रोहियों की मजबूत पकड़ रही है। इन्हें तुर्की सरकार का समर्थन हासिल है लेकिन सीरिया की सरकारी सेना के हाल के हमलों से विद्रोहियों के परे उखड़ रहे हैं। तुर्की की सेना भी आगे बढ़ते सीरियाई सैनिकों को



तुर्की समर्थित सीरिया के विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लड़ाके सरकारी बलों पर तोप से गोले दागते हुए। इदलिब प्रांत में सीरिया की रूस समर्थित सरकारी सेना विद्रोहियों से सीधे भिड़ गई है।

एएफ़पी

नहीं रोक पा रही है। मॉस्को रवाना होने से पहले एर्दौगन ने कहा, उनका उद्देश्य सीरिया में युद्धविराम लागू करना है। एर्दौगन अगर अपने उद्देश्य में कामयाब हुए तो इदलिब में सीरियाई सेना की कारवाई रुक जाएगी। लेकिन गुरुवार की बैठक से पहले रूस ने कहा है कि सीरिया में तुर्की के आक्रामक रुख के चलते तनाव बढ़ा है और हालात बिगड़े हैं।

उसने 2018 में हुआ संघर्षविराम तोड़ा है। अब तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही सीरियाई और रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। कई स्थानों पर तुर्की के सैनिक विद्रोहियों के मोर्चों पर जाकर इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने विवाद में जुड़ते हुए कहा कि सीरिया में शांति नहीं हुई तो वह रूस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है।

गृह मंत्री प्रीति के खेद जताने पर समर्थन में आए पीएम जॉनसन

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी के इस्तीफे के मामले में भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने खेद व्यक्त किया है। अधिकारी को इस दौरान मुश्किल का आरोप लगा था। फिलहाल मंत्री ने ऐसे सभी आरोपों को गलत बताया है। इमेल में कहा है कि वह साथ काम करने वाले सभी अधिकारियों–कर्मचारियों का गंभीरता से ध्यान रखती हैं और चाहती हैं कि उनकी टीम भी साथ आगे बढ़े। हमें सर फिलिप के इस्तीफा देने के फैसले पर खेद है। हमें पेशेवर अंदाज में साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे सरकार की योजनाएं आगे बढ़ पाएंगी और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ पाएगा। अधिकारियों के उर्पीड़न के मसले को विपक्षी लेबर पार्टी लगातार तूल दे रही है।

कहा, भारत की घटनाओं पर करीब से रखी जा रही निगाह

दंगों में हिंदू भी मरे

सदन में चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ केंजरवेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि वह इस बात से सदन को वाकिए कराएंगे कि दंगों में सिर्फ मुस्लिम नहीं मारे गए बल्कि हिंदू भी मरे हैं।

ना केवल उनके साथ मुश्किल मुद्दों पर चर्चा कर पाते हैं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों समेत अपनी चिंताएं उन्हें बता पाते हैं। हम घटनाओं पर करीब से नजर रखना जारी रखेंगे और जब उनके साथ हमारी चिंताएं होंगी तो उन्हें व्यक्त करेंगे।’ सरकार के इस बयान को हालांकि पाकिस्तानी मूल के सांसद ने खानापूर्ति बताया। पाकिस्तानी मूल की एक अन्य सांसद नुसरत गनी ने ब्रिटिश सरकार की चिंताओं को भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा– ईरान के प्रदर्शनों में मारे गए थे 23 बच्चे

पेरिस, एएफ़पी : मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि ईरान में पिछले साल नवंबर में भड़के हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 23 बच्चों की भी मौत हुई थी। संगठन के मुताबिक, इन हिंसक प्रदर्शनों में कुल 304 लोगों की मौत हुई थी।

पश्चिम एशिया में संगठन के निदेशक फिलिप लूथर ने बुधवार को कहा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोली मारने से 22 लड़कों और एक लड़की की मौत हुई थी। लड़कों की उम्र 12 से 17 साल के बीच जबकि लड़की की उम्र आठ से 12 साल के बीच थी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ नवंबर में पूरे देश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। हिंसक प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने दमनात्मक रवैया अपनाया था। इन प्रदर्शनों में जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार बच्चों के परिजनों को मुंह बंद रखने के लिए डरा-धमका रही है।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में एमनेस्टी ने ईरान के नवंबर में हुए विरोध प्रदर्शनों में हुई मौतों का आंकड़ा 304 बताया था जिसे ईरान ने झूठ करा दिया था। ईरान की ओर से एमनेस्टी के इन आंकड़ों को ‘पूरी तरह झूठ’ बताया गया था और इसे खारिज कर दिया था।

ग्रीस सीमा अशांत, आंसू गैस के गोले छोड़े

तुर्की की ढील की वजह से उसकी सीमा से शरणाथियों का यूरोपीय देश ग्रीस में दाखिल होना जारी है। बुधवार सुबह शरणाथियों को रोकने के लिए ग्रीस के सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी किया। ये शरणाथी सीरिया और अन्य अशांति मुस्लिम देशों से आए हैं, जो अभी तक तुर्की के शिविरों में रह रहे थे। यूरोपीय देशों ने एक समझौते के तहत इन शरणाथियों की सुविधाओं के लिए तुर्की को छह अरब यूरो (49 हजार करोड़ रुपये) दिए हैं। लेकिन अब सीरिया पर हमले कर रहा तुर्की यूरोप से आर्थिक और सेन्य सहयोग की मांग कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दौगन ने कहा है कि यूरोप को सीरिया में उसका साथ देने चाहिए। सहयोग न मिलने पर वह 40 लाख शरणाथियों को भेजने की धमकी दे रहा है। इसी के चलते ग्रीस में शरणाथियों के पहुंचने का सिलसिला कई दिन से जारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

14 राज्यों के प्राइमरी चुनाव में नौ में जीते पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेन, बाकी तीन उम्मीदवारों का बुरा हाल, तुलसी गार्बार्ड भी हारी

बिडेन और सैंडर्स में सिमटी डेमोक्रेट उम्मीदवारी की होड़

वाशिंगटन, एर्जेसिया : अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ अब पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और सीनेटर बर्नी सैंडर्स के बीच सिमट गई है। मंगलवार को 14 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनाव में इन दोनों नेताओं में ही मुख्य मुकाबला देखने को मिला। बाकी दावेदार मुकाबले से बाहर दिखाई दिए। इन राज्यों में से नौ में बिडेन ने जीत दर्ज की जबकि बाकी सैंडर्स के खाते में गए।

77 वर्षीय बिडेन ने 228 डेलीगेट्स वाले टेक्सास, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, अलाबामा, अरकंसास, ओक्लोहोमा, टेनेसी, मैसाच्युसेट्स और मिनिसोटा जैसे राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की। जबकि 78 साल के सैंडर्स ने 415 डेलीगेट्स वाले कैलिफोर्निया समेत उटाह, कोलोराडो और अपने गृहराज्य वर्मीट में परचम लहराया। इन राज्यों के आंतरिक चुनावों में बाकी तीन दावेदारों का बुरा हाल रहा। प्राइमरी चुनाव प्रचार पर 50 करोड़ डॉलर (करीब 3600 करोड़ रुपये) खर्च करने वाले मीडिया मुगल और न्यूयॉर्क



सुपर टयूजडे नाइट रैली के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करते डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार बर्नी सैंडर्स।

रायटर

के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग का हाथ खाली रहा। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गार्बार्ड भी अपनी छाप छोड़ने में विफल रहीं।

सीनेटर एंजिलाबेथ वारेन को अपने गृहराज्य मैसाच्युसेट्स में भी हार का सामना करना पड़ा।

सकता है। - एएनआइ